04 - फेमिसाइड में उलझी दुनिया की चुनौतियां चिंताजनक

05 - मंगल की ओर मानवता का अगला कदम



A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024

06 - क्षमता- 12 से 15 हजार, आवक 25 से 30 हजार क्विंटल...

केंद्रीय रेल मंत्री से सांसद आलोक शर्मा ने की भोपाल एक्सप्रेस के मथुरा स्टॉपेज की मांग



भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-90 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)



सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews


प्रसंगवश

# कनाडा व अमेरिका से भारत में रिवर्स ब्रेन ड्रेन की सम्भावना बढ़ रही

**प्रह्लाद सबनानी**

वैश्विक स्तर पर लगातार कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती दिखाई दे रही हैं, जिससे विशेष रूप से कनाडा एवं अमेरिका से भारत की ओर रिवर्स ब्रेन ड्रेन की सम्भावना बढ़ती जा रही है। कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी आंदोलन के चलते वहां निवासरत भारतीयों एवं मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं एवं भारतीयों एवं मंदिरों पर हो रहे इन हमलों पर लगाम लगाने में कनाडा की वर्तमान सरकार असफल सिद्ध हो रही है एवं इन हमलों को, राजनैतिक कारणों के चलते, रोकने की इच्छा शक्ति का अभाव भी दिखाई दे रहा है। इसके चलते भारत एवं कनाडा के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रिश्तों पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति तो यहां तक पहुंच गई है कि भारत ने कनाडा में अपने दूतावास में प्रतिनिधियों की संख्या को कम कर दिया है तथा भारत ने कनाडा को निर्देशित किया था कि वह भी भारत में अपने दूतावास में प्रतिनिधियों की संख्या को कम करे। भारत एवं कनाडा के बीच आज कूटनीतिक रिश्ते आज तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। साथ ही, कनाडा में आज सुरक्षा की दृष्टि से भी स्थितियां तेजी से बदल रही हैं तथा इसका कनाडा के आर्थिक विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके चलते भारतीय आज कनाडा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और भारत की ओर रूख कर रहे हैं।

दूसरी ओर, अमेरिका में डोनल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के पश्चात वहां पर अवैध रूप से रह रहे अन्य देशों के नागरिकों को अमेरिका से निकाले जाने की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की संख्या लगभग नगण्य सी ही है परंतु ट्रम्प प्रशासन द्वारा अब वीजा, एच1बी सहित, जारी करने वाले नियमों को और अधिक कठोर बनाया जा सकता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले कुल एच1बी वीजा में से 60 प्रतिशत से अधिक वीजा भारतीय मूल के नागरिकों को जारी किए जाते हैं। यदि इस संख्या में भारी कमी दृष्टिगोचर होती है तो अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को, उनकी पढ़ाई सम्पन्न करने के पश्चात यदि एच1बी वीजा जारी नहीं होता है तो उन्हें भारत वापिस आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार अमेरिका से भी भारतीयों का रिवर्स ब्रेन ड्रेन दिखाई पड़ सकता है।

भारत आज पूरे विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है, अतः भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास के कारण सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, उच्च तकनीकी क्षेत्रों, वाहन विनिर्माण उद्योग, फार्मा उद्योग, चिप विनिर्माण उद्योग, स्टार्ट अप, आदि क्षेत्रों में भारी मात्रा में रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं और भारत को इन क्षेत्रों में उच्च टेलेंट की आवश्यकता भी है। यदि कनाडा एवं अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त एवं उक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षित इंजीनीयर्स भारत को प्राप्त होते हैं तो यह स्थिति भारत के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रही है।

उक्त कारणों के अतिरिक्त आज अन्य देशों से भारत की ओर रिवर्स ब्रेन ड्रेन इसलिए भी होता दिखाई दे रहा है क्योंकि, भारत में आज मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी भी दृष्टि से भारत का आधारभूत ढांचा आज किसी भी विकसित देश की तुलना में कम नहीं है। साथ ही, भारत में, विकसित देशों की तुलना में, मुद्रा स्फीति की दर कम होने से, सामान्य रहन सहन की लागत तुलनात्मक रूप से भारत में बहुत कम है। अतः भारत में अमेरिका एवं कनाडा की तुलना में शुद्ध बचत दर भी अधिक है। हाल ही के समय में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। आज बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में बहुत ही कम लागत पर अमेरिकी अस्पतालों की तुलना में (अमेरिका की तुलना में तो 1/10 लागत पर) अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में तो शुद्ध हवा एवं शुद्ध पानी, जो स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने में सहायक होता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वरना, महानगरीय इलाकों में तो आज सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। विभिन्न देशों से उच्च शिक्षा प्राप्त एवं टेलेंटेड भारतीय जो भारत वापिस लौटे हैं, उन्होंने अपने नए प्रारम्भ किए गए स्टार्ट अप के कार्यालय दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए हैं।

भारत में बहुत लम्बे समय से मजबूत लोकतंत्र बना हुआ है एवं केंद्र में एक मजबूत सरकार, उद्योग एवं व्यापार को भारत में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं व्यापार के मित्रवत आर्थिक नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा में अपार वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। विकसित देशों में नागरिकों की औसत आयु 50 वर्ष से अधिक हो रही है जिससे श्रमिकों की संख्या इन देशों में लगातार कम हो रही है एवं श्रम लागत में भी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके कारण इन देशों में उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। हाल ही के समय में चीन भी इस समस्या से ग्रसित पाया जा रहा है। केवल भारत एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों में ही श्रम लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इसके कारण विश्व की कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भारत में करना चाहते हैं। भारत में उत्पादों का निर्माण कर इन उत्पादों को विश्व के अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। भारत का विदेशी व्यापार घाटा लगातार कम हो रहा है। आज विश्व के कई विकसित देशों में सामाजिक तानाबाना छिन्न भिन्न हो गया है एवं इन देशों के नागरिकों में मानसिक असंतोष की भावना लगातार बढ़ रही है एवं इन देशों की आधे से अधिक आबादी आज मानसिक बीमारीयों से ग्रसित है। जबकि इसके ठीक विपरीत भारत में हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों के अनुपालन से एवं संयुक्त परिवार की जीवनशैली के चलते भारतीय नागरिक मानसिक बीमारियों से लगभग पूर्णतः मुक्त रहे हैं एवं सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विकसित देशों के नागरिकों ने भौतिक विकास तो अधिक किया है परंतु मानसिक शांति खोई है। इन्हीं कारणों के चलते आज विश्व के कई देशों के नागरिक हिंदू सनातन संस्कृति को अपनाने की ओर लालायित दिखाई दे रहे हैं और वे भारत में बसने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। अतः विकसित देशों से भारत में रिवर्स ब्रेन ड्रेन आने वाले कल की सच्चाई है।

**(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)**

## हरियाणा के बॉक्सर की दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी

- कांग्रेस में हार के बाद भाजपा में शामिल हो चुके

हिसार (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हरियाणा के बॉक्सर विजेंदर सिंह दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब विजेंदर सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ एक फोटो शेयर की।

इस फोटो में विजेंदर पंच दिखाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि विजेंदर सिंह इससे पहले दक्षिण दिल्ली लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि, उस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अब वह बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन चर्चाओं पर विजेंदर सिंह के भाई मनोज बेनीवाल का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पार्टी जो जिम्मेदारी विजेंदर को देगी, वह अच्छे से निभाएगा। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने 2019 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी।

## सुप्रभात

रात की धड़कन जब तक जारी रहती है
सोते नहीं हम ज़िम्मेदारी रहती है
जब से तू ने हल्की हल्की बातें कीं
यार तबीअत भारी भारी रहती है
पाँव कमर तक धँस जाते हैं धरती में
हाथ पसारे जब ख़ुद्दारी रहती है
वो मंज़िल पर अक्सर देर से पहुँचे हैं
जिन लोगों के पास सवारी रहती है
छत से उस की धूप के नेज़े आते हैं
जब आँगन में छाँव हमारी रहती है
घर के बाहर ढूँढता रहता हूँ दुनिया
घर के अंदर दुनिया-दारी रहती है..।

**- शालिनी सिंह**

# मणिपुर में शांति बहाली में सेना का है बड़ा रोल

- आर्मी चीफ बोले-सेना में एक साथ काम करते हैं कुकी और मैतेई
- 13 दिन बाद जिरीबाम में अब खुलेंगे स्कूल, सर्च ऑपरेशन जारी

**पुणे (एजेंसी)।** मणिपुर हिंसा के बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सेना कुकी और मैतेई समाज के लोगों को एकजुट करने का काम कर रही है। उनका कहना है कि भारतीय सेना एक जाति विहीन आर्मी है।

यह आपसी तालमेल बढ़ाती है और मतभेद खत्म करती है। यहां सभी संस्कृति के लोग एक साथ काम करते हैं। जनरल द्विवेदी ने पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान मणिपुर में शांति बहाली के लिए आर्मी के पूर्व सिपाहियों के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जवान कुकी-मैतेई के बीच शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं।

दरअसल, मणिपुर में कई बार शांति बहाली के लिए कुकी और मैतेई समाज के एक्स-सर्विसमेन की रैलियां हुई हैं। हिंसा के 13 बाद कल से इंफाल वैली में 16 दिन से बंद स्कूल-कॉलेज फिर से खुल जाएंगे। दरअसल, जिरीबाम में 16 नवंबर को 3 बच्चों और 3 महिलाओं का शव मिलने के बाद इंफाल वैली के जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए थे। इंफाल में सुरक्षाबलों ने 94 चेकपॉइंट बनाए मणिपुर में सुरक्षाबलों ने पहाड़ी और घाटी जिलों के संवेदनशील इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए।

## सीएम यादव बोले-

# एमपी में खुलेंगे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट

### जर्मनी में कहा- यहां की आबादी वृद्धावस्था में, इन्हें वर्कर्स और हमें रोजगार की जरूरत

**भोपाल (नप्र)।** यूके की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 2 दिन 28 एवं 29 नवंबर तक जर्मनी के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने जर्मनी के बावेरिया स्टेट के मंत्री और स्टेट चांसलर-इन-चीफ डॉ. हरमन से मुलाकात की।

सीएम ने इस मुलाकात के बाद कहा, जर्मनी की आबादी बहुत थोड़ी सी है और इनमें भी ज्यादातर बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर इस अवस्था को पहुंचने के करीब हैं। जर्मनी में टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वर्कर्स की जरूरत है, हमारे यहां भी युवाओं को रोजगार की जरूरत है। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए भाषा की बाधा दूर करने के लिए हम एमपी में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलकर युवाओं को आगे बढ़ाएंगे।

सीएम जर्मनी में उद्योगपतियों से एमपी में निवेश की संभावनाओं पर भी बात करेंगे। इसके पहले यूके में सीएम को एमपी के लिए 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। वे तीन दिन यूके के दौरे पर रहे, जो बुधवार को ही पूरा हुआ।

### सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी तेजी से डेवलप हुआ

सीएम ने कहा, नई टेक्नोलॉजी के बल पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस ढंग से जर्मनी आर्थिक समृद्धशाली ताकत बनकर निकला है, ये दुनिया के सामने एक आदर्श उदाहरण है। जर्मनी की आबादी लगभग सवा आठ करोड़ है, लेकिन आज यह विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सीएम ने कहा, जर्मनी की टेक्नोलॉजी से हमारे यहां के उद्योगपति लाभ लें, खासकर ऑटोमोटिव सेक्टर में, इनके वाहन बहुत उन्नत प्रकार के हैं।

### सीएम ने ग्लोबल समिट के लिए दिया न्योता

सीएम ने कहा, हम जब वैश्विक स्तर की कॉन्क्लेव करेंगे, इसके लिए हमने इन्हें आमंत्रित किया है। हम यहां के उद्योगपतियों से बात करेंगे, कंपनियों से भी बात करेंगे। एक अच्छी बात उन्होंने कही कि एक-दूसरे के राज्यों में लोगों को टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने में हमारे अधिकारी स्तर पर जो कठिनाइयां आती हैं, वो भी कम होंगी और हम भी उसे कम करेंगे।

# हेमंत सोरेन चौथी बार बने झारखंड के सीएम

### अकेले शपथ ली, मंच पर राहुल, केजरीवाल, ममता समेत 10 पार्टियों के नेता रहे मौजूद

**रांची (एजेंसी)।** जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बन गए। उन्हें गुरुवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। समारोह में इंडिया की 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता शामिल हुए। इनमें राहुल गांधी, प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी के तेजस्वी यादव मौजूद रहे। दोपहर 3 बजे हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को हाथ पकड़कर समारोह स्थल ले गए। शपथ से पहले हेमंत ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक होगा। हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें न विभाजित किया जा सकता है, न ही शांत किया जा सकता है। हम झारखंडी हैं और झारखंडी झुकते नहीं हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिदो- कान्हू उद्यान में अमर वीर शहीद सिदो- कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थीं। वहीं, अर्जुन महतो के शहीद होने पर उनके भाई बलराम महतो को नियुक्ति पत्र दिया।

# अजमेर दरगाह में मंदिर होने के तीन आधार पेश

- हाईकोर्ट के जज की किताब का दिया गया हवाला

**अजमेर (एजेंसी)।** अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। किताब में इसका जिक्र है कि यहां ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं, जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहां शिव मंदिर रहा था। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) को नोटिस जारी किया है। 20 दिसंबर को उन्हें अपना पक्ष लेकर उपस्थित होना है।

# इंडियन नेवी ने की बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** इंडियन नेवी ने बुधवार को के-4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। यह टेस्टिंग न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से की गई थी। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका अपग्रेड वर्जन जल्द ही कमीशन किया जाएगा। अरिघात आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। अरिहंत की तुलना में अरिघात 3500 किलोमीटर की रेंज वाली के-4 मिसाइलों से लैस होगी।

**3,500 किलोमीटर की है रेंज,आईएनएस अरिघात से लॉन्चिंग**

इस सबमरीन का वजन 6 हजार टन (60 हजार क्विंटल) है। भारत ने तैयार की परमाणु मिसाइलों से लैस 3 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत कमीशंड है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी के 3 पर टेस्टिंग जारी है। इन सबमरीन के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती हैं। 2009 में पहली बार सांकेतिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया था। इसके बाद 2016 में इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 23 °c

न्यूनतम 18°c


# सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 29 नवंबर 2024


जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

## अडाणी पर लगे आरोपों को नॉर्वे-राजनयिक ने अमेरिकी अतिक्रमण बताया

**मुंबई (एजेंसी)।** नॉर्वे के राजनयिक और यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम के फॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोलहेम ने अमेरिकी सरकार की हाल ही में आई उस रिपोर्ट की आलोचना की है, जिसमें गौतम अडाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की

रिश्वत देने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे अमेरिकी अतिक्रमण कहते हुए रिपोर्ट की ग्लोबल मीडिया कवरेज पर बात करते हुए पूछा – अमेरिकी अतिक्रमण कब रुकेगा सोलहेम ने कहा कि आरोपों में वास्तविक रिश्वत पेमेंट या अडाणी ग्रुप के लीडर्स की संलिप्तता के सबूत नहीं हैं। न ही इस बात का कोई सबूत है कि अडाणी के अधिकारियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। आरोप केवल इस दावे पर आधारित है कि रिश्वत का वादा किया गया था या इस पर चर्चा की गई थी। इस अमेरिकी अतिक्रमण के लोगों के जीवन पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह अडाणी ग्रुप को लेकर अमरीकी चाल है।

## पायलट ने बॉयफ्रेंड से तंग आकर किया था सुसाइड

### नॉनवेज खाने से रोकता था, सड़क पर बेइज्जती की, नंबर ब्लॉक कर दिया था

**मुंबई (एजेंसी)।** मुंबई में महिला पायलट सुसाइड केस में नए खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बॉयफ्रेंड महिला को प्रताड़ित करता था। उसकी बेइज्जती की। दोनों के बीच नॉनवेज खाने को लेकर भी लड़ाई होती थी। लड़की के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित को 26 नवंबर को अरेस्ट किया था। महिला की पहचान

सृष्टि तुली के रूप में हुई। वह एअर इंडिया में पायलट थी। 25 नवंबर को सृष्टि का शव मुंबई में फ्लैट में मिला था। उसने डेटा केबल से फांसी लगाई थी। परिवार का आरोप- बॉयफ्रेंड लड़की से झगड़ा करता था सृष्टि के चाचा विवेक कुमार तुली की शिकायत के आधार पर पवई पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में कई बातें सामने आईं। आदित्य अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बुरा व्यवहार करता था। पिछले साल नवंबर में आदित्य चाचा की कार लेकर सृष्टि और उसकी बहन राशि को दिल्ली में शॉपिंग कराने ले गया था। मार्केट में दोनों के बीच बहस हुई। आदित्य ने राशि के सामने सृष्टि से गाली-गलौज की। गुस्से में कार से दूसरी गाड़ी को टक्कर भी मार दी।

# मध्य प्रदेश के 8 लाख आउटसोर्स अंशकालीन कर्मचारियों का दर्द

### 10 हजार की तनख्वाह और हर में पल नौकरी जाने का डर, 10 साल से नहीं बढ़ा वेतन

**भोपाल (नप्र)।** मध्य प्रदेश में बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग की जमीनी व्यवस्थाएं संभाल रहे लगभग 5 लाख आउटसोर्स व 3 लाख अस्थाई-अंशकालीन कर्मचारियों की अपनी व्यथा है। अव्वल तो 10 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा है और नौकरी भी निजी कंपनी के 'रहम' पर है। उन्हें साल 2019 में गठित वेज रिवीजन बोर्ड की सिफारिश का लाभ भी नहीं मिला। बोर्ड के कहने पर कमलनाथ सरकार ने वेतन में प्रतिमाह 1942 रुपए की बढ़ोत्तरी की थी, लाभ मिलने से पहले ही मप्र टेक्सटाइल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी और स्टे मिल गया। जिस पर 3 दिसंबर को सुनवाई होगी। 10 से 13 हजार की तनख्वाह पाने वाले इन कर्मचारियों को हर पल नौकरी जाने का डर रहता है।

रीवा मेडिकल कॉलेज के 5 कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए नौकरी से हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने अन्य कर्मचारियों की तरह दिवाली से पहले अक्टूबर का वेतन मांग लिया था। इस घटना ने कर्मचारियों को एकजुट कर दिया है और अब वेज रिवीजन की बात फिर होने लगी है। मई 2024 में गठित वेज रिवीजन बोर्ड की अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। इसे लेकर पिछले हफ्ते ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स व अस्थाई कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारी इंदौर में श्रमायुक्त से मिले चुके हैं। कर्मचारियों ने यह आरोप भी लगाया कि श्रम आयुक्त कार्यालय व मंत्रालय सहित ऐसे ही अन्य कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स और स्थाईकर्मियों को पूरा वेतन दिया जाता है, पर उसी विभाग के मैदानी कर्मचारियों को कम दिया जाता है। यह गड़बड़ी नियोक्ता एजेंसी करती हैं। वरिष्ठ कार्यालय के कर्मचारियों के मामले में उन्हें शिकायत का डर रहता है।

### मंत्रालय से पंचायत तक आउटसोर्स

कर्मचारियों की आउटसोर्स पर नियुक्ति का शुरू से विरोध हो रहा है। नियमित कर्मचारी कभी नहीं चाहते कि आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएं। फिर भी कम वेतन में काम चलाने के लिए राज्य सरकार ने धीरे-धीरे लगभग सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी रख लिए। अब उन्हें भी सम्मानजनक वेतन नहीं दे पा रही है। मंत्री स्टाफ, मंत्रालय, ऊर्जा, स्वास्थ्य वे विभाग और कार्यालय हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या में आउटसोर्स और अंशकालीन कर्मचारी काम कर रहे हैं।

### 2014 में निर्धारित वेतन दिया जा रहा

इन कर्मचारियों को वर्तमान में वर्ष 2014 में निर्धारित किया गया वेतन दिया जा रहा है। इसमें साल में दो बार 20 से 80 रुपए महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाता है। 2019 में 25त्न की वृद्धि हुई थी, जो लागू नहीं हो पाई। वर्तमान मूल्य सूचकांक के हिसाब से वेज रिवीजन किया जाता है, तो इन कर्मचारियों के वेतन में 3800 रुपए से अधिक की वृद्धि होगी। बता दें कि प्रत्येक 5 साल में वेज रिवीजन करने का नियम है और 2024 में इसका टर्न है।

## वंदे भारत के बाद इंडियन रेलवे अब देगा एक और नया गिफ्ट

- अब 280 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी भारतीय ट्रेनें

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** वंदे भारत की रफ्तार का मजा ले रहे भारतीयों को जल्द ही तेज रफ्तार ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके संकेत दिए हैं।

कहा जा रहा है कि इन नई ट्रेनों में ऑटोमैटिक दरवाजों समेत कई आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। खबर है कि इन नई ट्रेनों की रफ्तार 250 किमी प्रतिघंटा से भी ज्यादा की होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के साथ मिलकर हाईस्पीड ट्रेन बना रही है। ये खास ट्रेनें 280 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार हासिल कर सकेंगी। रेल मंत्री ने लोकसभा में बुधवार को बताया कि मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत आने के बाद रेलवे इस नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वंदे भारत की स्पीड 160 किमी प्रतिघंटा है। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के साथ सुधीर गुप्ता और अनंत नायक की तरफ से सवाल पूछा गया था। इसपर वैष्णव ने जवाब दिया, निर्माण की लागत करीब 28 करोड़ रुपये प्रति कार आएगी। इसमें कर शामिल नहीं हैं...। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेयर कार ट्रेन सेट्स में आधुनिक सुविधाएं होंगी।

## कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम 'कोटा' के लिए हलचल तेज

- कांग्रेस पर बढ़ा मुसलमानों को आरक्षण देने का दबाव

**बेंगलुरु (एजेंसी)।** कर्नाटक में मुसलमानों को 4 फीसदी आरक्षण का मुद्दा फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। खबर है कि हाल ही में हुए उपचुनावों में जीत के बाद कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम कोटा बहाल करने का दबाव बढ़ने लगा है। फिलहाल, इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोटा खत्म कर दिया था, लेकिन इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि, अब तक साफ नहीं है कि कर्नाटक में कोटा बहाल कब तक किया जाएगा। खास बात है कि साल 2023 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कोटा का मुद्दा कांग्रेस के लिए काफी अहम साबित हुआ था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अगुवाई में सरकार गठन में इसने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब कांग्रेस को उपचुनाव में भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिवाजीनगर से कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद का कहना है कि कोटा बहाल होगा।

## वायनाड से निर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने ली शपथ

### शपथ के साथ दिया बड़ा संदेश, हाथ में लिए रहीं संविधान

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** वायनाड लोकसभा सीट से चुनी गईं प्रियंका गांधी ने आज सांसद के तौर पर शपथ ली। कांग्रेस की नेता शपथ के दौरान हाथ में संविधान की कॉपी लिए रहीं। इस तरह उन्होंने संविधान वाले दांव को भी शपथ के साथ ही चलने की कोशिश की, जिस पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान नैरेटिव तैयार किया था। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि सरकार इसलिए 400 सीट चाहती है ताकि संविधान बदला जा सके और गरीबों का आरक्षण छीन

लिया जाए। इसके बाद जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस के सांसदों ने संविधान लेकर ही शपथ ली थी। अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद जैसे नेता भी संविधान की कॉपी लिए दिखे। उसी को अब प्रियंका गांधी ने भी आगे बढ़ाया है। राहुल गांधी खुद रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि सोनिया गांधी राज्यसभा की मेंबर हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट का उपचुनाव 4 लाख 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है।

## बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से कोर्ट का इनकार

### यूनुस सरकार बोली-संगठन के खिलाफ जरूरी कदम उठाएं

**ढाका (एजेंसी)।** बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने गुरुवार को इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद मोइनुउद्दीन ने बुधवार को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) के बारे में अलग-अलग समाचार पत्रों की रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। इन रिपोर्ट्स में कथित तौर पर इस्कॉन से जुड़े लोगों पर हिंसा भड़काने और चिटगांव में वकील सैफुल इस्लाम की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे थे। इस आधार पर मोइनुद्दीन ने अदालत से इस्कॉन पर बैन का स्वतः संज्ञान (स्वैच्छिक) आदेश देने का अनुरोध किया था। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के मुताबिक, याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस्कॉन सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, पारंपरिक हिंदू समुदायों पर अपनी मान्यताओं को थोपने और पिछड़ी हिंदू जातियों के सदस्यों को जबरन भर्ती करने के इरादे से धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा दे रहा है। गुरुवार को अदालत में इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने जस्टिस फराह महबूब और देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ को बताया कि सरकार इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठा रही है।

### 'बांग्लादेश' मामले में मोदी के साथ आईं ममता

**कोलकाता (एजेंसी)।** बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास को जेल भेजे जाने पर ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि इस पर केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं, वह चाहे जो कदम उठाए। ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि यह दूसरे देश का मामला है। इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। बनर्जी ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार को सुलझाना है और राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का पालन करेगी। बनर्जी ने कहा, 'बांग्लादेश एक अलग देश है। भारत सरकार इस पर गौर करेगी। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।



## देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे

- शिवसेना नेता ने कहा-कोई और बन सकता है डिप्टी सीएम

**मुंबई (एजेंसी)।** महाराष्ट्र की नई बनने वाली सरकार में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं होंगे। उन्होंने बुधवार को ही सीएम पद से अपना दावा छोड़ते हुए कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे, वह उन्हें और पूरी शिवसेना को स्वीकार होगा। तब से ही कयास लग रहे थे कि एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम होंगे, जबकि भाजपा से देवेंद्र



फडणवीस अब मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस बीच शिवसेना के नेता संजय शिर्सात का कहना है कि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट का हिस्सा तो होंगे, लेकिन वह डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। शिवसेना के लीडर ने पीटीआई से बातचीत में कहा, एकनाथ शिंदे शायद डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। ऐसी जिम्मेदारी एक ऐसे नेता पर फिट नहीं बैठती, जो मुख्यमंत्री रह चुका हो। यही नहीं उन्होंने कहा कि शिवसेना की ओर से राज्य सरकार में किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा।

### फडणवीस बोले- एक बार सीएम तय हो जाए, सब ठीक हो जाएगा

इस बीच निवर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि राज्य में महायुति एकजुट है। उन्होंने कहा, एक बार मुख्यमंत्री तय हो जाने के बाद, वह व्यक्ति राज्य मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देगा।' फडणवीस ने बाद में नागपुर में कहा कि महायुति के घटक दल एकजुट हैं। उन्होंने कहा, 'सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएंगे और हम अपने शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यदि किसी को संदेह है तो एकनाथ शिंदे ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।' उन्होंने कहा, '(एकनाथ) शिंदे साहब, (उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता) अजित दादा पवार और मैं साथ हैं।

## पुलिस की निगेटिव रिपोर्ट के बावजूद बनेगा पासपोर्ट

### हाई कोर्ट का आदेश, कहा-कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकते

**नईदिल्ली (एजेंसी)।** पासपोर्ट बनवाने या उसे रिन्यू कराने की कतार में लगे लोगों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस जांच की रिपोर्ट नकारात्मक आ जाए, तब भी पासपोर्ट बनने से नहीं



रोका जा सकता है। हाल ही में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट निगेटिव होना अपने आप में किसी नागरिक को पासपोर्ट पाने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करता है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पासपोर्ट प्राधिकरण पुलिस की रिपोर्ट से बंधी हुई नहीं है। सुनवाई करते हुए पीठ ने अपने फैसले में कहा,प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट किसी नागरिक को उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है।

## भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बना पुतिन का देश

### कभी 0.2 फीसदी थी हिस्सेदारी, अब टॉप पर पहुंचा रूस

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को बताया कि रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस अब भारत के कुल तेल आयात का 35 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आपूर्ति करता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के ऑयल एंड गैस अवॉर्ड्स समारोह में बोलते हुए, मंत्री ने बताया कि भारत के तेल स्रोतों में पिछले दो वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। फरवरी 2022 में



रूस से तेल आयात मात्र 0.2 प्रतिशत था, जो अब शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। पुरी ने कहा, काफी समय से रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) है। यह प्रतिशत महीने दर महीने बदलता रहता है, लेकिन यह 35 प्रतिशत से अधिक है।

**तेल आपूर्ति और ऊर्जा साझेदारी में बड़ा बदलाव-** हरदीप पुरी ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत की साझेदारियों के बदलाव पर जोर देते हुए कहा, कुछ देशों के साथ हमारे लंबे कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो कुछ से स्पॉट मार्केट में खरीद की जाती है। आगामी वर्षों में प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों में सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत और अमेरिका जैसे देश शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने ईंधन की कीमतों में कमी के मामले में वैश्विक स्तर पर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा,भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडरों की लागत 6 प्रति दिन और गैर- योजना घरों के लिए 14 प्रति दिन है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 2014 में बढ़ाया गया है।

## मध्य प्रदेश में 18 जजों के तबादले

### 11 डिस्ट्रिक्ट-सेशन जज बदले, 7 फैमली कोर्ट जज नियुक्त

**भोपाल (नप्र)।** एमपी हाईकोर्ट ने 18 जजों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 11 जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं, तो 7 जजों को फैमिली कोर्ट के खाली पदों पर पदस्थ किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल के अध्यक्ष नवीर अहमद खान को हरदा का जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।

## ऊर्जा मंत्री तोमर आज करेंगे विकास कार्यों का भूमि-पूजन

**भोपाल (नप्र)।** ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शुक्रवार 29 नवम्बर को ग्वालियर-15 विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में एक करोड़ 25 लाख रूपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे। मंत्री श्री तोमर उज्जवला योजना अन्तर्गत घरेलू गैस कनेक्शन का वितरण भी करेंगे।

## डबरा में एसबीआई का एटीएम ही उखाड़ ले गए बदमाश, अंदर थे 6 लाख रुपये

**डबरा (नप्र)।** अभी तक एटीएम मशीन को काटकर चोर रुपए चुराते थे। लेकिन अब वे पूरा का पूरा एटीएम ही उखाड़कर कर ले गए। शहर के पिछोर तिराहे पर स्थित एसबीआई एटीएम चोरी की घटना में बड़ा खुलासा हुआ है। एसबीआई शाखा ने पुलिस को सूचित किया है कि चोरी की गई एटीएम मशीन में 6 लाख रुपये थे। अज्ञात चोर बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को एटीएम मशीन को उखाड़कर फरार हो गए।

पुलिस प्रशासन के लिए यह घटना एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि यह डबरा में एटीएम चोरी की पहली बड़ी घटना नहीं है। हालांकि, पहले जिस घटना का उल्लेख किया जा रहा था, जिसमें 23 लाख रुपये की चोरी का दावा किया गया था, अब उसमें नया तथ्य सामने आया है। 2022 में हुई इस घटना में एटीएम को काटने की कोशिश की गई थी, लेकिन पैसे चोरी नहीं हुए थे। यह जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है।

## भोपाल में टेलीकॉम इंजीनियर के डिजिटल अरेस्ट का मामला

### उत्तर प्रदेश से की गई पहली गिरफ्तारी, आरोपी ठगी में इस्तेमाल सिम मुहैया करवाता था

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल में 12 नवंबर की रात को बजरिया इलाके के गायत्री नगर में रहने वाले टेलीकॉम इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करने के मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्रामीणों के आधार कार्ड को अपडेट करने के नाम पर ई-केवाईसी करता था और उनके नाम पर सिम कार्ड जारी कराता था। इन सिम कार्डों को वह साइबर ठगों को 1,000 रुपये प्रति सिम के हिसाब से बेचता था। इस तरीके से आरोपी ने लगभग 150 सिम अलग-अलग साइबर ठगों को बेचे हैं।

डिजिटल अरेस्ट होने के बाद क्राइम ब्रांच ने 13 नवंबर को इंजीनियर और उनके परिवार को घर से बाहर निकाला। इंजीनियर और उनका परिवार इस कदर घबराया हुआ था कि साइबर क्रिमिनल्स का वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद भी वे घर से बाहर नहीं निकले। ठगों ने उनसे 24 घंटे उनकी निगरानी में रहने के लिए कहा था। उनके मोबाइल पर किसका कॉल आ रहा था, ठगों को इसका पता तक चल रहा था। इस वजह से वे किसी का कॉल उठा नहीं पा रहे थे।

### 12 नवंबर को आया था कॉल,ठग बोले- नंबर बंद हुआ तो गिरफ्तारी होगी

एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि करारिया के गायत्री नगर में रहने वाले प्रमोद कुमार (38) प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में फील्ड इंजीनियर हैं। 12 नवंबर की शाम 4.15 बजे उनके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को ईओडब्लू का अधिकारी बताकर कहा कि आपके नंबर से अलग-अलग बैंक खातों में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन रकम का लेनदेन हुआ है। आपका नंबर बंद नहीं होना चाहिए। मैं मुंबई से हूं। नंबर बंद करने की हालत में भोपाल से गिरफ्तारी की जाएगी। ठगों को प्रमोद के मोबाइल में सेव कई जानकारियां पहले से पता थीं।

### दूसरे कॉल में मुंबई क्राइम ब्रांच का बताया

पहला कॉल डिस्कनेक्ट होने के कुछ ही देर बाद प्रमोद को दूसरे नंबर से वीडियो कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही स्क्रीन पर पुलिस यूनिफॉर्म में तीन लोग दिखे। उन्होंने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और कहा कि आपके नंबर से एक व्यक्ति से फिरौती मांगी गई है।

प्रमोद ने अपना पक्ष रखना चाहा तो उसे धमकाया गया। कहा आपने जो जुर्म किया है, इसके लिए 3.50 लाख रुपए का फाइन और दो साल जेल की सजा है।

प्रमोद की कंपनी के बॉस की सूचना पर पुलिस उनके घर पहुंची। इसके बाद उन्हें बाहर निकाला था।

### इंजीनियर से ठग बोले- भले आदमी हो, बचा लेंगे

ठगों ने प्रमोद से बातचीत करते हुए उनसे उनकी पूरी जानकारी हासिल की। इस बीच उनके मोबाइल पर वेटिंग पर जो कॉल आ रहे थे, वे भी ठगों को पता होते थे कि किसके कॉल हैं। इससे प्रमोद और भी घबरा गए थे।

ठगों ने उनसे कहा कि हम स्थानीय पुलिस की मदद से आपको गिरफ्तार करने वाले थे। भले आदमी लग रहे हो। बचना चाहते हो तो हमारी निगरानी में 24 घंटे तक रहना होगा। इस पर उन्होंने ने हामी भर दी।

आरोपियों के कहने पर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। रात 11.30 बजे तक ठगों की निगरानी में रहे। बाद में आरोपियों ने खुद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।

### इंजीनियर के घर पहुंचे बॉस, पुलिस को दी सूचना

डर की वजह से बुधवार सुबह 11.30 बजे तक प्रमोद ने किसी का कॉल पिक नहीं किया। ऑफिस की मीटिंग भी अटेंड नहीं की। इससे एक दिन पहले प्रमोद एक्जीट के दौरान अटेंडेंस अपडेट किए बगैर ही ऑफिस से शाम को निकलने वाले थे।

शंका होने पर उनके बॉस प्रदीप ने उन्हें कॉल किए। कई कॉल करने पर भी उन्होंने कॉल को पिक नहीं की। तब प्रदीप के साथ अनहोनी की आशंका के चलते उनके घर पहुंचे। प्रमोद ने गेट खोलने से इनकार कर दिया।

ऐसे में उनके बॉस ने भोपाल क्राइम ब्रांच को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रमोद को रेस्क्यू किया। उन्हें बताया कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा था। पुलिस की समझाइश के बाद वे नॉर्मल हुए और पत्नी - बच्चों के साथ घर से बाहर निकले।

### मंत्रालय में की विभागीय कार्यों की वृहद समीक्षा

# स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी और जन-सुलभ बनाने समय-सीमा में पूर्ण करें कार्य: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

**भोपाल (नप्र)।** उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधोसंरचना विकास एवं प्रशासनिक सुधार के सभी कार्यों को तय समयसीमा में पूरा किया जाए। जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और जनसुलभ बनाया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की वृहद समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त श्री तरुण राठी और उप सचिव श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वीकृत पदों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्ती किये जाने की प्रक्रिया की समीक्षा की और औपचारिकताओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रीवा मेडिकल कॉलेज में कैथलैब के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे

क्षेत्रीय मरीजों को उन्नत उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही रीवा और सतना मेडिकल कॉलेज, एमवाई हॉस्पिटल इंदौर में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिये।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कैबिनेट के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मेडिकल कॉलेजों में पे-प्रोटेक्शन और नवीन जिलों के जिला अस्पतालों में पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। उन्होंने प्रदेश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए नियमों और निर्देशों में अपेक्षित सुधार किए जाने की कार्रवाई के निर्देश दिये।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पदों पर नियुक्ति के लिए मानकों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिये। बैठक में वर्षों से निलंबित डॉक्टरों के प्रकरण में विचार के लिए गठित विशेष समिति की बैठक आयोजित कर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा। बॉन्ड अवधि पूरी कर चुके डॉक्टर्स को एनओसी जारी करने और उनके दस्तावेज लौटाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के विषय पर विमर्श किया और प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिये।

### भोपाल मंडल में 341 फॉग सेफ डिवाइस का उपयोग

# अब कोहरे में ट्रेन संचालन सुरक्षित रहेंगी

**भोपाल (नप्र)।** मंडल में कोहरे के मौसम में संरक्षित रेल संचालन के लिए मंडल रेल प्रबंधक भोपाल श्री देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (कर्षण परिचालन) श्री सचिन शर्मा के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रेल संचालन से जुड़े कर्मचारियों को विशेष निर्देश के साथ-साथ बाधा रहित ट्रेन संचालन में उपयोगी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में कोहरे के दौरान भोपाल मंडल में लोको पायलटों को लोको में उपयोग हेतु 341 फॉग सेफ डिवाइस (FSD) दिए गए हैं।

**फॉग सेफ डिवाइस क्यों उपयोग किया जाता है?-** कोहरे के दौरान दृश्यता बेहद कम हो जाती है, जिससे लोको पायलटों के लिए सिग्नल और ट्रैक की स्थिति का सही तरीके से आकलन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में फॉग सेफ डिवाइस लोको पायलटों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपकरण सिग्नल की सटीक जानकारी प्रदान करता है साथ ही अलग स्थानों पर लगे सिग्नल एवं पर दाहिनी ओर लगे सिग्नल को विशेष रूप से चेतावनी के साथ इंगित करता है, जिससे ट्रेनों का संचालन सुरक्षित और निर्बाध रूप से हो सके।

**फॉग सेफ डिवाइस कैसे काम करता है?-** फॉग सेफ डिवाइस एक जीपीएस आधारित उपकरण है, जो लोको पायलट को उनके मार्ग पर सिग्नलों और अन्य प्रमुख स्थानों की सटीक जानकारी देता है। यह उपकरण सिग्नल की दूरी, और ट्रेन की गति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, यह लोको पायलट को अलर्ट भी देता है जब ट्रेन किसी सिग्नल के करीब होती है।

### फॉग सेफ डिवाइस के उपयोग के लाभ

1. **सुरक्षित संचालन:** यह लोको पायलट को कोहरे के दौरान भी सिग्नल की स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है।
2. **समय की बचत:** उपकरण के निर्देशों के माध्यम से ट्रेनें सटीक गति और दिशा में चल सकती हैं, जिससे समय की बचत होती है।
3. **पायलटों का आत्मविश्वास:** FSD का उपयोग लोको पायलटों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बेहतर ढंग से ट्रेनों का संचालन कर सकते हैं।
4. **यात्रियों की सुरक्षा:** यह उपकरण यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करता है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि लोको पायलटों को कोहरे के समय फॉग सेफ डिवाइस के साथ ट्रेनों की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे अथवा अपने विवेकानुसार निम्नतम बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिग्नलों की सूचना दर्शाने वाले बोर्डों को दुबारा पेंट किया जा रहा है अथवा चमकीली पट्टी लगाई जा रही है। कोहरे के समय दृश्यता कम होने पर लोको पायलटों की सहायता हेतु स्टेशन मास्टरों द्वारा विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट (वीटीओ) के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। इससे लोको पायलटों को स्टेशन पास होने की जानकारी मिलेगी।

ट्रैकमैन द्वारा लोको पायलटों को रास्ते में सिग्नल होने की चेतावनी देने के लिए पटाखे का उपयोग करने के निर्देश और पर्याप्त मात्रा में पटाखे दिए गए हैं। सर्दियों में जिन स्थानों पर प्रायः पटरियों के फ्रैक्चर की संभावना होती है, वहां अत्यधिक सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। पटरियों की गहनता से जांच की जा रही है। इसके लिए अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार रेल खंडों में गति प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां पटरियों में फ्रैक्चर की संभावना रहती है, वहां विशेष कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की जा रही है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने गुरूवार को महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्षरत, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवानदास सबनानी, जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी, भगतसिंह कुशवाह एवं संयुक्त माली सैनी मरार समाज के अध्यक्ष जीपी माली उपस्थित रहे।

## मोटा अनाज, धान उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कार्यशाला आज

**भोपाल (नप्र)।** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज उपार्जन की तैयारी तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पात्र परिवारों को राशन वितरण पर चर्चा के लिये 29 नवम्बर को प्रातः 10 बजे से कार्यशाला होगी। कार्यशाला आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में आयोजित की जायेगी। कार्यशाला में सभी जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन और क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन शामिल होंगे।

## चौथी मंजिल से गिरकर ऑटो चालक की मौत

### दोस्त बोला- सवारी से विवाद हुआ, किराया मांगने उसके पीछे गया था; मारपीट हुई

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल के कमला नगर थाना इलाके में नया बसेरा मल्टी की चौथी मंजिल से गिरकर ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। वह एक सवारी को छोड़ने नया बसेरा पहुंचा था। सवारी ने किराया देने से इनकार कर दिया।

मृतक के दोस्त का दावा है कि वह सवारी के पीछे किराया मांगने चौथी मंजिल तक गया था। वहां फ्लैट पर सवारी के परिचित भी मौजूद थे। किराया मांगने पर बहस हुई, जो मारपीट में बदल गई। इसी दौरान दोस्त फ्लैट की बालकनी से गिर गया। मामला संदिग्ध है जब उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, तो मोहल्ले वालों ने रोक लिया। अधिक खून बहने से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस का कहना है कि फिलहाल मर्ग कायम किया गया है। युवक किन हालात में गिरा, इसकी जांच की जा रही है। घटना बुधवार शाम की है, जबकि देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया।

**परिवार का इकलौता बेटा था दीपेश-** दीपेश सिसोदिया अपने पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक छोटी बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। पिता कलेक्टर ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। दीपेश की मौत के बाद उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है। दोस्तों और परिजनों ने सन्नी, उसकी बहन और साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है।

## अपनी ही पार्टी की विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस

### बीना एमएलए निर्मला की सदस्यता रद्द करने की मांग, वे 6 महीने भाजपा के साथ

**भोपाल (नप्र)।** कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी की विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कांग्रेस ने मांग की है कि सागर जिले के बीना से विधायक सप्रे ने दल-बदल किया है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। सप्रे 6 महीने से भाजपा के साथ हैं, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है।

विधायक निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 5 मई को राहतगढ़ में सीएम डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंचीं थी। तब से वे कांग्रेस से दूरी बनाते हुए भाजपा के साथ हैं, लेकिन औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। इसी वजह से आधिकारिक तौर पर अब भी वो कांग्रेस की विधायक हैं।

अब कांग्रेस ने निर्मला की सदस्यता खत्म कराने को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गुरुवार को भास्कर से चर्चा में इसकी पुष्टि की। सिंघार ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को जुलाई में हमने पत्र दिया था। विधानसभा ने कागज गुमा दिए। 90 दिन बाद भी अध्यक्ष ने कोई निर्णय नहीं लिया इसलिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। 5 मई को विधायक निर्मला सप्रे को सीएम डॉ. मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी।

**वीडी बोले- निर्मला ने विधानसभा को जवाब दिया है-** बुधवार को बीजेपी प्रदेश

अध्यक्ष वीडी शर्मा से मीडिया ने पूछा कि आपने निर्मला सप्रे को बीजेपी में शामिल किया है तो अब उन्हें बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्यों लटका कर रखा है? इसके जवाब में उन्होंने कहा- मुझे जो जानकारी है उन्होंने शायद विधानसभा को लिखकर दिया कि मेरा कांग्रेस से मोह भंग हुआ है। मैं विधायक हूं। जनता की सेवा के लिए चुनकर आई हूं। जनता के लिए मेरा अधिकार है कि मुख्यमंत्री से मिलूं।

**जीतू बोले- निर्मला को इस्तीफा देकर चुनाव लड़वाएं-** निर्मला सप्रे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा- मैं मोहन यादव को चुनौती दे रहा हूं कि आप इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो तो निर्मला सप्रे को इधर से उधर क्यों घुमा रहे हो। आप में दम होगा तो आप जीतोगे, हम जनता के बीच में जाएंगे हम में दम होगा तो हम जीतेंगे। जनता के ऊपर छोड़ो, वह क्या करना चाहती है। आप पहले लोकसभा चुनाव में उन्हें ले गए और हाथ ऊंचा करा दिया कि ये हमारी पार्टी में आई।

# किसानों को हर हाल में मिले गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक : शिवराज सिंह चौहान

### ● नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के मामले में दोषियों को नहीं बख्शें, कड़ी सजा दिलवाएं राज्य ● श्री चौहान ने कहा कि हम किसानों की शिकायतों को लेकर मूकदर्शक बने नहीं रह सकते ● किसानों की भलाई के लिए सभी विभाग संयुक्त अभियान चलाएं

**भोपाल।** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के किसानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता की खाद, बीज और कीटनाशक मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री चौहान ने अपने मंत्रालय की विभागवार समीक्षा के दौरान इस संबंध में अफसरों को किसानों की व्यापक भलाई के लिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी व प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। श्री चौहान ने कहा कि कई राज्यों में ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई प्रभावी नहीं होने वे छूट जाते हैं, इस बारे में वे स्वयं शीघ्र ही राज्य सरकारों से बात करेंगे, ताकि राज्यों के स्तर पर प्रभावी कार्रवाई निरंतर की जाती रहे और जो कोई भी दोषी पाया जाएं, उन्हें कड़ी सजा मिल सकें, जिससे कि ऐसे घृणित कृत्य रूक सकें। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश के आम किसानों के हित में वे इस संबंध में किसी भी हालत में सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं।

कृषि भवन, नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय की विभागवार समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि कीटनाशक, बीज एवं फर्टिलाइजर किसी भी हालत में किसानों को बेहतर गुणवत्ता के ही मिलना चाहिए। राज्यों में प्रवास के दौरान किसान हमसे शिकायत करते हैं कि उन्हें कई बार घटिया क्वालिटी के ये आदान मिलते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बैठक में सख्त लहजे में कहा कि एक जागरूक जनप्रतिनिधि के तौर पर हम किसानों की इन शिकायतों को लेकर मूकदर्शक बने नहीं रह सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नकली या घटिया किस्मों के कीटनाशक, खाद एवं उर्वरकों पर प्रभावी नियंत्रण के ठोस उपाय किए जाना चाहिए।

कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी फसल सीजन के मद्देनजर भी किसानों को इस संबंध में राहत मिलना चाहिए, इसके लिए वे शीघ्र ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से इस बारे में राज्यों के स्तर पर ही प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। समीक्षा के दौरान श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि ऐसे नकली आदान बनाने-बेचने वालों पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो इस दौरान यह बात सामने आई कि कई राज्यों के स्तर पर जांच-पड़ताल तथा अभियोजन के स्तर पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अधिकांश दोषी लोग बरी हो जाते हैं या उन्हें बहुत कम दंड मिलता है, जिस पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे मुख्यमंत्रियों व कृषि मंत्रियों से भी इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करवाने के लिए बात करेंगे, राज्यों में प्रभावी कार्रवाई किसी भी सूरत में की जाना चाहिए। घटिया खाद, बीज व कीटनाशक के मामले में बड़े विक्रेताओं और निर्माताओं पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाना चाहिए तथा मौजूदा कानूनों, नियम-प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि कीटनाशकों, खाद एवं उर्वरकों के अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से एक अभियान चलाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खाद, बीज एवं कीटनाशकों के बारे में संयुक्त अभियान चलाने की कार्ययोजना बनाकर अतिशीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि इस अभियान को, करोड़ों किसानों के हित में बिना देरी के प्रभावी रूप से देशभर में, राज्य सरकारों के साथ मिलकर संचालित किया जा सकें। श्री चौहान ने कहा कि किसानों से भी इस संबंध में इनपुट लिया जाएं, क्योंकि वास्तव में तो किसान प्रभावित होते हैं और घटिया क्वालिटी के आदानों से फसलों को नुकसान होता है।

## संपादकीय

# संविधान की आत्मा की रक्षा

सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना से बाद में जोड़े गए 'धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी' शब्द हटाने की मांग से सम्बन्धित याचिकाओं को खारिज कर संविधान की आत्मा की रक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये दोनों शब्द संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इन शब्दों को संविधान में 42वें संशोधन (1976) के जरिए शामिल किया गया था और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं।

बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा कि संविधान में दर्ज 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं को बताते हैं। इन्हें हटाना उचित नहीं है। संविधान को उसके मूल उद्देश्यों से अलग करने का कोई भी प्रयास मंजूर नहीं। उल्लेखनीय है कि पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य की दायर याचिकाओं में कहा गया था कि 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को संविधान में शामिल करना गैर जरूरी और अवैध है। ये शब्द लोगों की निजी स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं पर असर डालते हैं। हालांकि कोर्ट के स्पष्ट फैसले के बावजूद कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। मसलन स्वतंत्र और संप्रभु भारत ने अपना लिखित संविधान 1949 में अपनाया था। लेकिन उस संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नहीं थे। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द शामिल किए गए थे। संविधान की प्रस्तावना में यह संशोधन उस वक्त किया गया था, विपक्ष बड़े पैमाने पर जेल में था। दूसरे, इस संशोधन के तीन साल पहले 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था कि संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी संविधान की प्रस्तावना में संविधान को आत्मार्पित करने की तारीख से संशोधन कर उसमे ये दो नए शब्द जोड़े गए। कहा जाता है कि ये दोनों शब्द तत्कालीन इंदिरा सरकार ने वामपंथियों के दबाव में जोड़ें। यहां सवाल उठता है कि कोई संशोधन पिछली तारीख से कैसे उचित है और दूसरा ये कि अगर ये शब्द अनिवार्य थे तो संविधान के रचनाकारों ने प्रस्तावना में इन्हें क्यों नहीं रखा। माना जाता है कि संविधान निर्माताओं का मानना था कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्दों में निहित भावना स्वतः समाहित है। इसके लिए स्वतंत्र रूप से इन शब्दों का उल्लेख आवश्यक नहीं है। ऐसे में धर्मप्रधान देश भारत के धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र करने का क्या मतलब है। हालांकि कई जानकारों का मत है कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल इन शब्दों की समय सापेक्ष व्याख्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता अर्थात् सभी धर्मों के प्रति समभाव से लिया जाना चाहिए न कि किसी भी धर्म को न मानने से। इसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रयोग पूरी दुनिया में फेल हो गए। ऐसे में समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य अब लोक कल्याणकारी राज्य से लिया जाना चाहिए, जो वर्तमान सरकारों द्वारा लागू लोक-लुभावन योजनाओं से परिलक्षित होता है। साथ ही हमने अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। इसे रोका नहीं जा सकता। इसी संदर्भ में सीजेआई ने कहा कि 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' दो अभिव्यक्तियां 1976 में संशोधनों के जरिए बनाई गई थीं। ये कहना कि ये संविधान 1949 में अपनाया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले से मौजूद तर्क माने जाते हैं तो वे सारे संशोधनों पर लागू होंगे। इतने सालों के बाद प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह सवाल भी किया कि इतने साल बाद इस मुद्दे को क्यों उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

## नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

# फेमिसाइड में उलझी दुनिया की चुनौतियां चिंताजनक

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अन्तरराष्ट्रीय दिवस की 25वीं वर्षगाँठ मनायी गयी। विश्व में महिला अधिकारों के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि हर दिन, 140 महिलाओं व लड़कियों को उनके ही परिवार के सदस्य जान से मार देते हैं। हमें कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा- हमारी लड़ाई अभी ख़त्म होने से बहुत दूर है। यह जो हर मिनट में 140 लिंग आधारित हिंसा की बात की जा रही है, यह सचमुच बहुत ही संवेदनशील बात है। बहुत ही झकझोर देने वाली बात है। पृथ्वी पर असुरक्षित महिलाओं की मौजूदगी में यदि विश्व की मानव बिरादरी खुश हो रही है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई और बात हो ही नहीं सकती। अबसे अहम् बात यह है की लिंग आधारित हिंसाएँ उनके अपने कर रहे हैं और वे सह रही हैं। बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई के लिए प्लैटफ़ॉर्म सन 1995 में तैयार करने की प्रतिबद्धता का घोषणा-पत्र था। उसके 30 साल भी धीरे-धीरे बीत गए हैं और अब भी धरती पर महिलाओं की रुदन, आँसू, व खून के प्यासे लोग सक्रिय हैं।

हिंसक होती सभ्यता ने महिलाओं पर सबसे ज्यादा जुर्म ढाए और उनके हितों को अनदेखा किया है। ज़ल्दबाजी में बार-बार शपथ लेती विभिन्न मंच पर क्रूरता की मिसाल आज की सभ्यता ने इनके झूठ को पकड़ लिया है और यह साबित हो चुका है की महिलाओं के लिए पूरे विश्व में बार-बार केवल झूठ बोला जाता रहा है। यदि ऐसा न होता तो आज महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के उन्मूलन के लिए अन्तरराष्ट्रीय दिवस की 25वीं वर्षगाँठ पर जारी रिपोर्ट में फ़ेमिसाइड यानी लैंगिक कारणों से महिलाओं व लड़कियों को जान से मार दिए जाने के वैश्विक संकट पर तत्काल कार्रवाई का आहवान न किया जाता।

फ़ेमिसाइड यानी लैंगिक वजहों से महिलाओं व लड़कियों को जान से मार दिए जाने की घटनाएँ, सीमाओं, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और संस्कृतियों से परे है। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप, इसकी गम्भीरता में अन्तर हो सकता है। रिपोर्ट यह बताती है कि अफ़्रीका में अंतरंग साथी हिंसा और पारिवारिक कारणों से सम्बन्धित महिलाओं की हत्या की सबसे अधिक दर दर्ज की गई। अफ्रीका में 2023 में 21 हज़ार 700 महिलाओं की हत्या हुई। जर्मनी की फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस के 2023 के आंकड़े खंगालने पर पता चलता है कि जर्मनी में 2023 में 155 महिलाओं की हत्या उनके पार्टनर या पूर्व पार्टनर ने की। इसके बाद अमेरिका और ओशीनिया का स्थान रहा। यूरोप और अमेरिका में, फ़ेमिसाइड के क्रमशः 64 प्रतिशत और 58 प्रतिशत मामले सामने आए, जिसमें से अधिकांश पीड़ितों को उनके अंतरंग साथियों के हाथों मारा गया था। इसके विपरीत, अफ्रीका और एशिया में महिलाओं के अपने साथियों की तुलना में, परिवार के सदस्यों द्वारा मारे जाने की अधिक सम्भावना नज़र

आई, जिसे लैंगिक भेदभाव के लिए ज़िम्मेदार सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयाम का सूचक माना जाता है।

हद तो यह है कि अगर महिलाओं को, महिला होने के नाते मारा जाता है, तो इन अपराधों को वही कहना चाहिए जो वे हैं अर्थात् फेमिसाइड। इन फेमिसाइड को रिश्ता टूटने की वजह से होने वाली दुखद घटना या ईर्ष्या के कारण हुई घटना नहीं कहा जा सकता। ये हत्याएं हैं और इन्हें गंभीरता से पूरे विश्व को लेना चाहिए। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ़ सक्रिय एक वैश्विक अभियान जो दुनिया भर में महिलाओं एवं लड़कियों को हिंसा व असमानता से निपटने के खिलाफ खड़ा हुआ है वह अब फेमिसाइड है, ऐसा कहा जा सकता है। इस पर विश्व चिंतित तो नज़र आ रहा है लेकिन विश्व में महिलाओं के खिलाफ चल रहे इस षड्यंत्र के मनोविज्ञान पर यदि फोकस किया गया तो ही यह हत्या का सिलसिला समाप्त होगा, वरना हर वर्ष जो फेमिसाइड के नए आंकड़े आ रहे हैं या आएंगे, उनमें अभिवृद्धि ही होनी है, वे कम नहीं होंगे। फेमिसाइड इसलिए आज की वैश्विक चुनौती है और इसके प्रभाव जो दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं वे महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और उनके जीवन के अधिकार को छीन रहे हैं जो व्यापक पैमाने पर महिला अधिकारों के हनन का मामला है।

सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी-2030 में लैंगिक समानता के लिए लक्ष्य 5 को हासिल करने की दूरी अब केवल हमसे पाँच साल दूर है। विश्व अपने चकाचौंध में मग्न है। मजाबादी समाज का उदय हो रहा है और हिंसा की शिकार महिलाएं हो रही हैं। वैश्विक सभ्यताओं का आज गठबंधन हो रहा है, अच्छी बात है लेकिन हिंसा के लिए यदि ज्यादा तेजी से हो रहा है, तो यह मनुष्यता के लिए और महिलाओं की स्वतंत्रता व उनकी शांति के लिए खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने कहा कि फेमिसाइड एक वैश्विक महामारी बन गई है क्योंकि राज्य लैंगिक हिंसा के पीड़ितों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। लैंगिक हिंसा रोकथाम हेतु विशेष दूत मॉरिस टिडबॉल-बिंज़ का कहना है कि महिलाओं की हत्या एक वैश्विक महामारी जैसी त्रासदी है। हर साल, ट्रांस महिलाओं सहित हजारों लड़कियों और महिलाओं को उनके लिंग के कारण दुनिया भर में मार दिया जाता है और कई और लोगों को लैंगिक हिंसा से मौत का खतरा होता है। राज्य पीड़ितों के जीवन की प्रभावी ढंग से रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। उनके जीवन को सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य में विफल राज्य आखिर क्या चाहते हैं? विगत वर्ष जब महासभा को अपनी रिपोर्ट टिडबॉल-बिनज़ ने सौंपी थी तो उसमें भी जोर देकर कहा था कि लिंग आधारित हत्याएं, लिंग आधारित हिंसा के मौजूदा रूपों की एक चरम और व्यापक मौजूदगी देखने को मिल रही है। एक फोरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में रिपोर्ट टिडबॉल-बिनज़ ने दण्ड से मुक्ति को संबोधित करने, पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय प्रदान करने और रोकथाम में योगदान देने के लिए स्त्री-हत्या की जांच के लिए मानकों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को दोहराया।

इस फेमिसाइड के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई के लिए एक पुकार पूरी दुनिया में हो रही है। फेमिसाइड से इस दुनिया की मुक्ति के चाहे जितने भी उपक्रम हुए हैं, वे नाकाफी हैं। ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रकार का मकैनिज्म तैयार करें जो इस त्रासदी से महिलाओं को बचा सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में आज जो आंकड़ा प्रति पल 140 का है वह बढ़कर 250 भी हो सकता है। सोचिये फिर आदि आबादी का क्या होगा? ऐतिहासिक रूप से आंकड़े में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को अपना प्रभुत्व दिखा रहा है। महिलायें उनके हाथों हिंसा की शिकार हो रही हैं। एक बड़ी बात जो विचार करने योग्य है वह है पितृसत्तात्मक समाज ही क्या इस त्रासदी का ज़िम्मेदार है? क्या महिलाएं इस हिंसा में खुद नहीं झोंक रही हैं, विचार इस पर करने की आवश्यकता है। पहले जब बहुत से देशों में समाज में बहुत सारी वर्जनाएं थीं, देह से मुक्ति स्त्री-स्वतंत्रता का विशिष्ट विषय नहीं था तो इतनी हिंसाएँ कम से कम नहीं होती थीं। भारत जैसे देश में तो यह कदाचित ना के बराबर था क्योंकि यहाँ परिवार जैसी संस्था में महिलाओं को फेमिसाइड का ग्रास नहीं बनना पड़ता था। अब भारत में भी उत्तर आधुनिकता और स्त्री मुक्ति की छटपटाहट पश्चिम जैसी हो रही है और स्त्रियाँ उसी तरह खुद को देखने के लिए आतुर हो रही हैं। पश्चिम का प्रभाव ज्यादा होने लगा है तो फेमिसाइड से उन्हें बच पाना कठिन हो रहा है।

ऐसे में, एक वैश्विक मैकेनिज्म की जो ज़रूरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, उसे गंभीर होकर बनाना पड़ेगा। उसे इस प्रकार से तैयार करना होगा जो स्त्रियों में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा घेरा बना सके और राज्य भी अपने लिए जिम्मेदारियां सुनिश्चित करें।

## चुनाव परिणाम विश्लेषण

रमेश कुमार 'रिपु'

लेखक पत्रकार हैं।

# झारखंड में चौंकाने वाले परिणामों की वजहें

महाराष्ट्र में महायुति रिकार्ड मतों से जीती मगर झारखंड में बीजेपी सारे दांव अपना कर भी नहीं जीत सकी। ऐसी कौन सी वजह रही है जिस वजह से भगवा छतरी नहीं तनी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से भाजपा झारखंडियों को नहीं भाई। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हैरान है कि राज्य में आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान के बाद भी आखिर पार्टी की इतनी करारी हार कैसे हो गयी। 81 सीटों वाले झारखंड में एनडीए को 22 जबकि इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें मिली। जबकि अंत तक यही माना जा रहा था कि चुनावी लड़ाई में बीजेपी का पलड़ा भारी है।

झारखंड में बीजेपी का सह प्रभारी बनने के बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने झारखंड के संथाल परगना इलाके में कथित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ की बात को जोर शोर से उठाया। अन्य बीजेपी नेताओं ने लव और लैंड जिहाद की बात की। यह दावा किया कि झारखंड के आदिवासी इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिये आ रहे हैं। यहां की आदिवासी महिलाओं से शादी कर उनकी संपत्ति हड़प रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में घुसपैठ के मुद्दे को उठाया था। लेकिन यहां के वोटर इसे मुद्दा ही नहीं माना। और नाराज होकर इंडिया गंठबंधन को वोट कर दिया। बीजेपी घुसपैठ मुद्दे को चुनावी औजार मान कर बड़ी भूल कर बैठी।

बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान आदिवासियों की रोटी, माटी,बेटी की हिफाजत को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। बाकी मुद्दों को बीजेपी ने पूरी तरह नजर अंदाज कर दिया। चुनाव नतीजों से पता चलता है कि संथाल परगना इलाके में बीजेपी की यह रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो गयी। बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। हालांकि उत्तरी छोटा नागपुर इलाके में पार्टी को थोड़ा सा फायदा हुआ। यहां 25 में से 14 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलीं।

**घुसपैठिये तक सिमटी बीजेपी-** इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि झारखंड के चुनाव में बीजेपी के पास कई मुद्दे थे। जिन्हें वह उठा सकती थी। जैसे बेरोजगारी, नौकरियों की कमी, हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से धन की बरामदगी, भर्ती परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवारों की मौत। लेकिन वह जनता से जुड़े मुद्दों को हाशिये पर रख कर सारा ध्यान घुसपैठ पर ही केंद्रित किया।

महतो समुदाय के उभरते हुए नेता जयराम महतो ने कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी और एनडीए को नुकसान पहुंचाया। महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को कम से कम 11 सीटों सिल्ली, बोकारो, गोमिया, गिरिडीह, टुंडी, इचागढ़, तमार,चक्रधरपुर, चंदनकियारी, कांके और खरसावां पर मिले वोट पर हार जीत के अंतर ज्यादा हैं। सिर्फ एक सीट डुमरी में इसने झामुमो को नुकसान पहुंचाया। डुमरी सीट से जयराम महतो चुनाव जीते हैं। जयराम महतो के राजनीति में आने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी की सहयोगी पार्टी आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) को हुआ है। आजसू को इस चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। जबकि 2019 में उसने दो सीटें जीती थी। चुनाव में आजसू के प्रमुख सुदेश महतो खुद भी सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए।

झारखंड में मैय्या सम्मान योजना बीजेपी के हार की सबसे बड़ी वजह थी। छह लाख वोट

महिलाओं के ज्यादा पड़े पुरुषों की तुलना में। चुनाव में 91.16 लाख महिलाओं ने जबकि 85.64 पुरुषों ने वोट डाला। इस लिहाज से महिलाओं ने करीब 6 लाख वोट ज्यादा डाले। इस योजना के तहत 21 से 49 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। झामुमो ने मैय्या सम्मान योजना का चेहरा हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन को बनाया। कल्पना ने इस योजना को झारखंड की महिलाओं के बीच में पहुंचाने के लिए पूरे राज्य में लगातार बैठकें और सभाएं की।

वैसे बीजेपी आदिवासियों के हक की बातें करती है। लेकिन झारखंड चुनाव में परिणाम बताते हैं कि आदिवासी उससे छिटक गया। झारखंड की विधानसभा में 28 सीटें जबकि लोकसभा की 5 सीटें आरक्षित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी लोकसभा में आरक्षित पांच सीटों में एक भी नहीं जीती थी। 28 आरक्षित विधानसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ एक सीट पर जीत पाई है। इससे ऐसा लगता है कि आरक्षित सीटों पर बीजेपी को बहुत काम करना है।

झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनने से एक बात साफ है कि आदिवासी समुदाय बीजेपी के साथ नहीं जुड़ पाया। जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने बड़े पैमाने पर आदिवासियों तक पहुंचने की कोशिश की थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। बीजेपी ने आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा के जन्म स्थान खूंटी में स्थित उलिहातू पहुंचे थे। झारखंड के आदिवासी वोटर को अपनी तरफ बीजेपी को करना चाहती है तो यहां उसे और काम करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई बड़े आदिवासी नेताओं की पत्नियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी चुनाव हार गईं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार गए।

हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव की तरह बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट झारखंड में वैसा नहीं था। इस वजह से बीजेपी वोटरों तक अपना पैठ नहीं बना पाई। इसके अलावा टिकट वितरण को लेकर भी नाराजगी रही। सात विधानसभा सीटों पर पार्टी ने गलत टिकट बांटे। कुछ सीटों पर बीजेपी बागियों से निपटने में भी फेल रही। योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बंटेगे नारे की खूब चर्चा हुई, लेकिन हिन्दू वोटों को झारखंड में नहीं जोड़ पाई। जिससे बीजेपी यहां हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा कामयाब नहीं हो सकी।

# हार की समीक्षा में व्यापार-धारा पर चिंतन

## कटाक्ष

डॉ. प्रदीप मिश्र

लेखक व्यंग्यकार हैं।

चुनाव में मिली जबरदस्त हार से मिले घाव, अभी हरे ही थे कि आलाकमान ने नेताजी को हार की समीक्षा-बैठक में बुलवा लिया। बैठक के बाद मैंने पूछा, 'आपने आलाकमान को अपनी हार का कारण क्या बताया?' नेताजी बोले, 'मैंने स्पष्ट कहा कि, 'विपक्ष के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से हम रोक नहीं पाए, इसलिए हार गए।'

- 'मतलब विपक्षी प्रत्याशी को आप चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते थे?'

- 'बिल्कुल! हम जानते थे कि वह जिस जाति का है, उसके सारे वोट उसी को मिलने हैं। और उसका जीतना बिल्कुल तय है।'

- 'आप उसे चुनाव लड़ने से रोक क्यों नहीं पाए?'

- 'अब कोई फोकट में तो जीता-जिताया चुनाव छोड़ता नहीं। दान-दक्षिणा देकर लुभाना पड़ता है?'

- 'तो आपने दान-दक्षिणा क्यों नहीं दी?'

- 'पार्टी ने हमें टिकट दिया था तो दान-दक्षिणा देने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। लेकिन पार्टी ने अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई।'

- 'तो आप दे देते!'

- 'किसी कंडीडेट को बिठाना इतना सरल थोड़ी होता है। पहाड़ जैसा बैलेंस दीजिए। सम्मानजनक पोस्ट का इंतजाम कीजिए। ये सब कंडीडेट अकेले के बूते थोड़ी होता है? पार्टी ने हाथ नहीं लगाया तो वह चुनाव में खड़ा रहा। और मैं हार गया।'

-'बैठक में आपने पार्टी से क्या डिमांड रखी?'

-' मैंने कहा कि चुनाव हारने से भविष्य में मेरी व्यापार-धारा का जो नुकसान होगा, उसकी क्षतिपूर्ति पार्टी को करना चाहिए।'

-' विचारधारा या व्यापार-धारा?' मैंने स्पष्ट जानना चाहा।

-' देखो सारा कुछ सिर्फ व्यापार-धारा ही है। चुनाव हारने से उसी के प्रवाह में कमी आएगी। पार्टी को चाहिए था कि धारा के उसी प्रवाह को वेगवान बनाए रखने का दायित्व उठाए।'

-' पार्टी ने क्या कहा?'

- ' पार्टी ने कहा, वह सिर्फ विजेता की व्यापार-धारा की जिम्मेदार है। हारने वाले के लिए पार्टी की विचारधारा ही अमूल्य-निधि है। चलो निकलो, दरवाजा खुला है।' कहकर वे खामोश हो गए।

सुना है , अपनी व्यापार-धारा के प्रवाह को गति देने के लिए नेताजी, अब नई विचार-धाराओं की तलाश में जुटे हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

**प्रधान संपादक**
उमेश त्रिवेदी
**कार्यकारी प्रधान संपादक**
अजय बोकिल
**संपादक (मध्यप्रदेश)**
विनोद तिवारी
**वरिष्ठ संपादक**
पंकज शुक्ला
**प्रबंध संपादक**
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

## हास्य-व्यंग्य

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

# लालसिंग दाँततोड़े का कचरा कांड

या र तुम यह बताओ कि दुनिया में क्या मियां बीवी में झगड़ा नहीं होता है! और कौन बीवी झगड़ा होने पर अपने आदमी को कचरा घोषित कर देती है!! 'ललसींग दाँततोड़े ने आते ही शिकायत छोड़ी ।

आपका झगड़ा हुआ क्या?'

'हुआ नहीं रे चल रहा है। तीन हफ्ते हो गए। दोनों तरफ से बम और मिसाइलें चल रहे हैं। उसका मायका अमेरिका है और हम पड़ोसियों पर निर्भर हैं। पड़ोसी कमबख्त मजा पूरा लेते हैं लेकिन मदद कुछ नहीं करते। तुम भी पड़ौसी हो!'

'झगड़ा किस बात पर हुआ?'

'यह तो पता नहीं, भूल भाल गए। लेकिन कोई ना कोई बात तो होगी ही झगड़े की। हमारे यहाँ तो शुरुआत की जरूरत रहती है बस, उसके बाद तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत नप जाता है।'

'तो आप भी यार दाँततोड़े ! दीवार से सिर क्यों मारते हो हमेशा। उस रास्ते पर जाना ही क्यों जिसमें आपके कचरे हो जाते हैं।... अभी आप कचरे का कुछ कह रहे थे।'

'हाँ, झगड़े में हम बाहर आ कर चिल्लाते है । इस्टाइल है हमारा । पिछले हफ्ते उसने मुझे कचरा घोषित कर दिया। घोषणा इतनी जोर की थी कि आसपास के सारे लोगों ने सुन लिया। मोहल्ले भर के बच्चे अब मुझे कचरा-अंकल बोलने लगे हैं। कल मिसेस शुक्ला आई तो वह बार-बार मुझे 'कचरा भाई साहब' कह रही थी। सुबह जब कचरा गाड़ी आती है तो लोग घरों से झांक कर देखते हैं।'

'आप भी यार कचरा जी, ...जरा पॉजिटिव सोचा करो। कचरा कोई मामूली चीज नहीं होती है आजकल। बिजली बनाते हैं उससे। बचपन में आपने वह पाठ भी तो पढ़ा होगा स्कूल में, 'घूरे से सोना बनाओ'। घूरा मतलब कचरा ही तो होता है।'

'देखो मुझे लग रहा है कि अब तुम मेरे मजे ले रहे हो! तुम पर गुजरती तो तुम्हें पता चलता। इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। याद रखो कल को तुम्हारे यहाँ भी मिसाइलें उड़ सकती हैं ।'

'छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो भाई दाँततोड़े इसी में भलाई है।'

'मेरे अकेले के नजअंदाज करने से कुछ थोड़ी होता है। कल किसीको फोन लगा कर कह रही थी कि अखबार में जाहिर सूचना छपवा दो कि दाँततोड़े कचरा आदमी है, इससे सावधान रहें। इस तरह तो सारा शहर मुझे कचरे के नाम से जाने लगेगा।'

'अरे तुम टेंशन मत लो यार। दस दिनों में फेमस हो जाओगे, हाथ आगे बढ़ा के कहना मजे में - माय सेल्फ लालसिंग दाँततोड़े 'कचरा नहीं'।'

'अरे भैया आज बाल बाल बचा मैं । वो सुबह कचरे की गाड़ी में डालने पर आमादा थी । वह तो अच्छा हुआ कि कचरे वाले ने पूछा कि गीले में डालूँ या सूखे में। यह कुछ समझ नहीं पाई और कचरे की गाड़ी आगे बढ़ गई।'

'तुम तो ऐतिहासिक आदमी हो गए यार दाँततोड़े । मैं तो समझता था कि भारत में अभी तक सिर्फ एक ही आदमी का कचरा हुआ है और अभी तक हो रहा है। जबकि उस बेचारे की शादी भी नहीं हुई है।'

'उसकी छोड़ो मेरी बताओ कल फिर गाड़ी वाला आएगा और कहीं इन्होंने मुझे गीले या सूखे में डालना तय कर लिया तो!'

'गीले में डलवाए तो तुम मना कर देना एकदम साफ-साफ। ठंड का मौसम है यार। सूखे में रहोगे तो सुखी रहोगे।'

'मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि कल जब कचरे की गाड़ी आए तो तुम आ जाना यार। सारे पड़ोसी भी उसकी तरफ है कहीं कचरे में डलवा ही ना दे।'

'तुम भी यार आदमी हो या फटा पजामा!!'

'तुम भी कैसे आदमी हो!! कुछ खाने-पीने को पूछो घर का। बाहर का खा खा के मेरा पेट कचरा हुआ जा रहा है।'

'दाँततोड़े इससे पहले कि तुम खुद अपना कचरा कर लो माफी मांग लो चुपचाप । माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सॉरी ही बोल दो। सॉरी की कोई वैल्यू है क्या आजकल। लोग पीक की तरह कहीं भी थूक देते हैं।'

'वह नहीं मानेगी पुतीन कहीं की। कोई बड़ा मध्यस्थ लगेगा तभी बात बनेगी। ... दिल्ली में कोई पहचान है क्या ?'

अंतरिक्ष उड़ान

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

# मंगल की ओर मानवता का अगला कदम

पृथ्वी के बगल में इंसानों के लिए सदा से ही आकर्षण का केन्द्र रहा एक खूबसूरत लाल ग्रह मौजूद है, जिसे 'रेड प्लेनेट' अथवा 'मंगल' के नाम से जाना जाता है। वैसे तो रात होते ही आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं लेकिन मंगल ऐसा ग्रह है, जो रात के समय लाल रंग का दिखाई देता है। इसी लाल ग्रह को ज्यादा से ज्यादा समझने और इसके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रतिवर्ष 28 नवम्बर को 'लाल ग्रह दिवस' (रेड प्लेनेट डे) नासा और उसके जैसे सभी अंतरिक्ष विज्ञान संस्थानों द्वारा मनाया जाता है। यह दिवस 28 नवम्बर 1964 को नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा अंतरिक्ष यान 'मेरिनर-4' के प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है, जो कई असफल मिशनों के बाद मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। करीब आठ महीने की यात्रा करने के बाद यह अंतरिक्ष यान अंततः 14 जुलाई 1965 को लाल ग्रह पर पहुंचा था। 28 नवम्बर 1964 को नासा ने जब पहली बार 'मेरिनर-4 रोबोटिक इंटरप्लेनेटरी प्रो' लांच किया था, तब अनौपचारिक छुट्टी की घोषणा की गई थी और सभी ने नासा की इस सफलता को उत्साहपूर्वक मनाया था।

मेरिनर-4 को फ्लाई-बाय के दौरान डेटा एकत्र करने, ग्रहों की खोज और मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अवलोकन को सक्षम करने तथा उस डेटा को पृथ्वी पर लोगों को वापस रिले करने के लिए बनाया गया था। अपने 228 दिनों के सफर को सफलतापूर्वक तय करने के बाद मेरिनर-4 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना था, जिसे नासा द्वारा मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया था। उसी स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने प्रस्तुत की थी।

अब तक 14 मंगल मिशन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं, जहां मानव निर्मित वस्तुएं इस ग्रह पर उतरी। ये सभी मंगल ग्रह से जुड़ी अलग-अलग जानकारियां पृथ्वी तक भेजते हैं। भारत भी इसरो के जरिये मंगल ऑर्बिट तक पहुंचने के अपने 'मंगल मिशन' में सफल हो चुका है। मंगल को जानने के लिए अब तक दुनियाभर में शुरू किए गए दो तिहाई अभियान असफल रहे हैं लेकिन भारत 24 सितम्बर 2014 को

मंगल पर पहुंचने के साथ ही विश्व में अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश तथा सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना था। पृथ्वी से मंगल की निकटतम दूरी 54.6 मिलियन किलोमीटर है और यह ग्रह जब पृथ्वी के करीब आता है तो इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इस छोटे से ग्रह का आयतन पृथ्वी के अनुमानित आयतन का महज 15 प्रतिशत है जबकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 10 प्रतिशत और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 37 प्रतिशत है। इसके कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पृथ्वी से तीन गुना ज्यादा ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं।

सूर्य से चौथा ग्रह 'लाल ग्रह' यानी मंगल है और मंगल तथा पृथ्वी का गहरा संबध माना जाता रहा है। यह बुध ग्रह के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, जिसे रोमन देवता के नाम पर 'मार्स' नाम दिया गया जबकि हिन्दू वैदिक धर्म ग्रंथों में इसे 'मंगल' कहा गया है। चूंकि मंगल ग्रह का रंग रक्त से जुड़ा है, इसलिए प्राचीन रोमन और यूनानियों ने इसे लाल ग्रह कहा था। वास्तव में उनकी पौराणिक कथाएं इस ग्रह को युद्ध के देवता के रूप में प्रस्तुत करती हैं। मंगल ग्रह को दूरबीन से देखने वाले पहले व्यक्ति गैलीलियो गैलीली थे। माना जाता है कि करीब 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ था, जो धूल एवं गैसों से भरा था और उसमें लोहे जैसे भारी तत्व भी मौजूद थे। उसी समय मंगल ग्रह का भी निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी ने अधिकांश लोहे को अपनी ओर खींचा और लोहे सहित अन्य तत्व भी उसकी कोर में समा गए। नासा का कहना है कि मंगल के कोर में भी लोहा है लेकिन हल्के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ लोहा इसकी ऊपरी सतह पर भी रह गया। मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है और अपने साथी स्थलीय ग्रहों की ही तरह इसमें भी एक केन्द्रीय कोर, एक चट्टानी आवरण और एक ठोस परत है।

धूल भरी, ठंडी, रेगिस्तानी दुनिया में इसका वातावरण बहुत पतला है। मौसमों, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों, घाटियों, विलुप्त ज्वालामुखी और इस बात के प्रमाण होने के साथ-साथ कि यह एक समय और भी अधिक सक्रिय था, मंगल एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी के कारण, मंगल ग्रह पर ऐसे मौसम का अनुभव होता है, जो अत्यधिक तापमान से बना होता है और तापमान -191 से 81 डिग्री फारेनहाइट तक जा सकता है। लाल ग्रह के बारे में जानने के लिए कई एस्ट्रोनॉमी क्लब की भी शुरुआत की गई है, जो मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारियों को एक-दूसरे से बांटने का काम करते हैं।

भारतीय वैदिक सभ्यता में माना गया है कि पृथ्वी और मंगल के बहुत गुण आपस में मिलते हैं। सूर्य के चारों तरफ घूमने की इनकी गति भी एक-दूसरे से काफी मिलती-जुलती है। जिस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है, उसी प्रकार मंगल के चारों ओर भी दो चंद्रमा ('फोबोस' और 'डेमोस') चक्कर लगाते हैं। मंगल ग्रह के चारों ओर कोई वलय नहीं हैं। कई अध्ययनों से पता चल चुका है कि मंगल ग्रह पृथ्वी की स्थलाकृति से काफी मिलता-जुलता है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह अलग-अलग मौसम हैं लेकिन वे पृथ्वी पर मौसम की तुलना में अधिक समय तक रहते हैं। चूंकि मंगल ग्रह के बहुत से गुण पृथ्वी की तरह ही हैं, इसीलिए पृथ्वी के पर्यावरण की तरह मंगल के पर्यावरण को समझकर यह माना जाता है कि बहुत साल पहले मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव हुआ होगा और यह भी माना जाता है कि भविष्य में भी मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। सूर्य से बहुत दूर होने के कारण मंगल की कक्षा पूरी होने की गति बहुत धीमी है और इसी कारण मंगल ग्रह पर एक वर्ष में करीब 687 दिन बीतेंगे, जो पृथ्वी पर एक वर्ष से लगभग दोगुना समय है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में मंगल ग्रह को 1.88 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी का करीब एक-तिहाई है और गुरुत्वाकर्षण के विभिन्न खिंचाव के परिणामस्वरूप ही यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 100 पाउंड है तो अंतरिक्ष में उसका वजन केवल 38 पाउंड ही होगा।

यह जानना भी बहुत दिलचस्प है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? दरअसल यह आकाश में एक लाल सितारे के रूप में दिखाई देता है और इसकी सतह भी महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से भरी धूल से ढ़की हुई होती है। मंगल ग्रह की सतह पर पाए जाने वाले तत्वों के कारण ही यह ग्रह लाल रंग का है। नासा के मुताबिक मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा में मौजूदगी है और वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार ऑक्सीजन तथा नमी के सम्पर्क में आने पर पृथ्वी पर लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है, ठीक उसी प्रकार मंगल की मिट्टी में मौजूद लौह खनिज में जंग लग गया है और उसी कारण यह लाल नजर आती है। मंगल की सतह पर काफी मात्रा में लोहा है और जब यह ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे आम भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। पृथ्वी अपने वायुमंडल के कारण नीले रंग की दिखाई देती है लेकिन मंगल का जंग जैसा लाल रंग इसकी मिट्टी में ऑक्सीकृत लोहे के कारण आता है। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह पर बहुत सारी चट्टानें लोहे से भरी हुई हैं और जब वे बाहरी वातावरण के सम्पर्क में आती हैं तो ऑक्सीकरण करती हैं और लाल हो जाती हैं। जब उन चट्टानों से जंग लगी धूल वायुमंडल में फैलती है तो इससे मंगल ग्रह का आकाश लाल या गुलाबी दिखने लगता है। आयरन ऑक्साइड अथवा आयरन रस्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण ही मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है और इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है।

पर्यावरण

बाल मुकुन्द ओझा

लेखक स्तंभकार हैं।

# जल संकट से खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्थाओं को खतरा

भारत में जल संकट एक गंभीर मुद्दा है, जो जनसंख्या वृद्धि, तेज़ी से शहरीकरण और जल प्रबंधन की अक्षमता के कारण उत्पन्न हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम हो रही है। पानी हर व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है और सभी को स्वच्छ जल सुनिश्चित किए बिना स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। जल की उपलब्धता और इसकी स्वच्छता में कमी से सुविधाहीन लोगों के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर अधिक असर पड़ता है। ग्लोबल कमिशन ऑन द इकोनामिक्स ऑफ वाटर की एक हालिया रिपोर्ट में वैश्विक जल संकट की चेतावनी दी गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक मांग आपूर्ति से 40 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है, जिससे खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्थाओं को खतरा है। भारत के लिये जो पहले से ही अंतर-राज्यीय जल विवादों और संरक्षण चुनौतियों से जूझ रहा है, यह रिपोर्ट जल संकट को दूर करने के लिये निर्णायक नीति सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। मूडीज़ रेटिंग्स ने भी चेतावनी दी है कि भारत में बढ़ती जल कमी, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्राकृतिक आपदाएँ कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक परिचालन सहित कई क्षेत्रों को बाधित कर सकती हैं। जल का महत्व केवल व्यक्तिगत उपयोग तक ही सीमित नहीं है; यह कृषि, उद्योग, और ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि में सिंचाई के बिना फसलों की वृद्धि असंभव होती है, जबकि उद्योगों में पानी का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं और कूलिंग के लिए किया जाता है। हाइड्रोपावर परियोजनाओं में भी जल ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। भारत में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वर्ष 2001 में 1,816 घन मीटर से घटकर 2011 की जनगणना के अनुसार 1,545 घन मीटर हो गई। केंद्रीय जल आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 तक जलस्तर और घटकर 1,434 घन मीटर तथा वर्ष 2050 तक 1,219 घन मीटर हो जाएगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2014 के बाद से धरती पर पीने योग्य पानी की मात्रा में अचानक कमी आई है, और तब से यह कमी लगातार बनी हुई है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि यह बदलाव इस बात का संकेत है कि पृथ्वी के महाद्वीप सूखे जैसे हालात में प्रवेश कर चुके हैं। रिसर्च के मुताबिक, साल 2015 से लेकर 2023 तक धरती में उपलब्ध मीठे पानी, जिसमें झीलों, नदियों का पानी शामिल है, 2002 से 2014 के बीच के औसत से 1,200 क्यूबिक किलोमीटर कम हो गया है। सूखा पड़ने पर खेतों में ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, और इससे खेतों और शहरों को ज्यादा पानी के लिए भूमिगत जल पर निर्भर होना पड़ता है। इस कारण भूमिगत जल का स्तर गिरने लगता है। बारिश और बर्फबारी से ये जल स्रोत फिर से नहीं भर पाते और इसके बाद और अधिक भूजल निकाला जाता है, जिससे पानी की आपूर्ति और भी कम हो जाती है।

मानव का अस्तित्व जल पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर कुल जल का अढ़ाई प्रतिशत भाग ही पीने के योग्य है। इनमें से 89 प्रतिशत पानी कृषि कार्यों एवं 6 प्रतिशत पानी उद्योग कार्यों पर खर्च हो जाता है। शेष 5 प्रतिशत पानी ही पेयजल पर खर्च होता है। यही जल हमारी जिन्दगानी को संवारता है। देश और दुनिया में पीने योग्य मीठे पानी की उपलब्धता लगातार कम हो रही है। मीठा पानी जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पीने के लिए, कृषि कार्यों में, उद्योगों में और स्वच्छता के लिए आवश्यक होता है। मीठा पानी मुख्य रूप से नदियों, झीलों, झरनों और भूमिगत जल भंडारों (जैसे कुएं और जलाशय) में पाया जाता है। दुनिया में मीठे पानी के स्रोत सीमित हैं, और जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या के कारण इसके स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। पानी की खपत की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है लेकिन दूसरी तरफ भूजल का दोहन भी उतनी तेजी से हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या विस्फोट और परंपरागत जल स्त्रोतों के अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल का स्तर लगातार कम होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व के कुल भूजल का 24 फीसदी इस्तेमाल करता है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से जल स्तर कम हो रहा है उससे भविष्य में संकट और गहरा हो सकता है। धरती का करीब तीन चौथाई हिस्सा पानी पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ तीन फीसदी हिस्सा ही पीने योग्य है। भारत अपनी जल-जरूरतों की पूर्ति के लिए सबसे ज्यादा भू-जल पर ही निर्भर है। यह ग्रामीण एवं शहरी घरेलू जलापूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

अभियान

ललित गर्ग

लेखक पत्रकार हैं।

# बाल विवाह मुक्ति बेटियों को खुला आसमान देगा

देश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने, बढ़ते बाल-विवाह से प्रभावित बच्चों के जीवन को इन त्रासद परम्परागत रूढ़ियों की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिये सरकार ने बाल-विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करके एक सराहनीय एवं स्वागतयोग्य उपक्रम से हिम्मत और बदलाव की मिसाल कायम की है। यह एक शुभ संकेत एवं श्रेयस्कर जीवन की दिशा है। यह किसी समाज के लिये बेहद नकारात्मक टिप्पणी है कि सदियों के प्रयास के बावजूद वहां बाल विवाह की कुप्रथा विद्यमान है। यहां यह विचारणीय तथ्य है कि समाज में ऐसी प्रतिगामी सोच क्यों पनपती है? क्यों लोग परंपराओं के खूंटे से बंधकर अपने मासूस बच्चों एवं बचपन से खिलवाड़ करते हैं? हमें यह भी सोचना होगा कि कानून की कसौटी पर अस्वीकार्य होने के बावजूद बाल विवाह की परंपरा क्यों जारी है? 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' की शुरुआत दूरगामी मानवीय सोच से जुड़ा एक संवेदनशील आह्वान एक नई सुबह की आहट एवं क्रांति के विस्फोट की संभावना है। यह अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक संकल्प है, एक रोशनी है, एक मंजिल है, एक सकारात्मक दिशा है। एक वादा है देशभर में बाल विवाह पर जागरूकता फैलाने और समाप्त करने का। यह नये भारत-सशक्त भारत की बुनियाद है। बाल विवाह रोकने के तमाम कार्यों, योजनाओं और कानूनों के बावजूद अगर कामयाबी नहीं मिल रही है, तो जाहिर है, एक विशेष अभियान छेड़कर केन्द्र सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। यह राष्ट्रीय अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गई प्रमुख योजना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की सफलता से प्रेरित है, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लड़कियों के बीच शिक्षा, कौशल, उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं बेटियों की आशाओं, आकांक्षाओं, संकल्पों से भरे सपनों की उड़ान को खुला आसमान देने में सक्षम होगा।

यह सुखद बात है कि बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 2029 तब बाल विवाह की दर को पांच प्रतिशत से नीचे लाने के मकसद से विशेष कार्य योजना बनाने का आग्रह किया है। यह बचपन की मासूमियत छीनने वाली 'बालविवाह' की बेड़ियों को तोड़ते हुए जागृति का एक शंखनाद किया है, एक समाज-क्रांति के बीज को रोपा गया है। सभी जानते हैं कि कम आयु के बच्चे अपने भविष्य के जीवन के बारे में परिपक्व फैसला लेने में सक्षम नहीं होते। साथ ही वे इस स्थिति में भी नहीं होते कि उनके जीवन पर थोपे जा रहे फैसले का मुखर विरोध कर सकें। उनके सामने आर्थिक स्वावलंबन का भी प्रश्न होता है। लेकिन अभिभावक क्यों इस मामले में दूरदृष्टि नहीं रखते? सही मायने में बाल विवाह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ही है। इसीलिये बाल-विवाह पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कानून परंपराओं से ऊपर है। कोर्ट का कथन तार्किक है कि जिन बच्चों की कम उम्र में शादी करा दी जाती है क्या वे इस मामले में तार्किक व परिपक्व सोच रखते हैं?

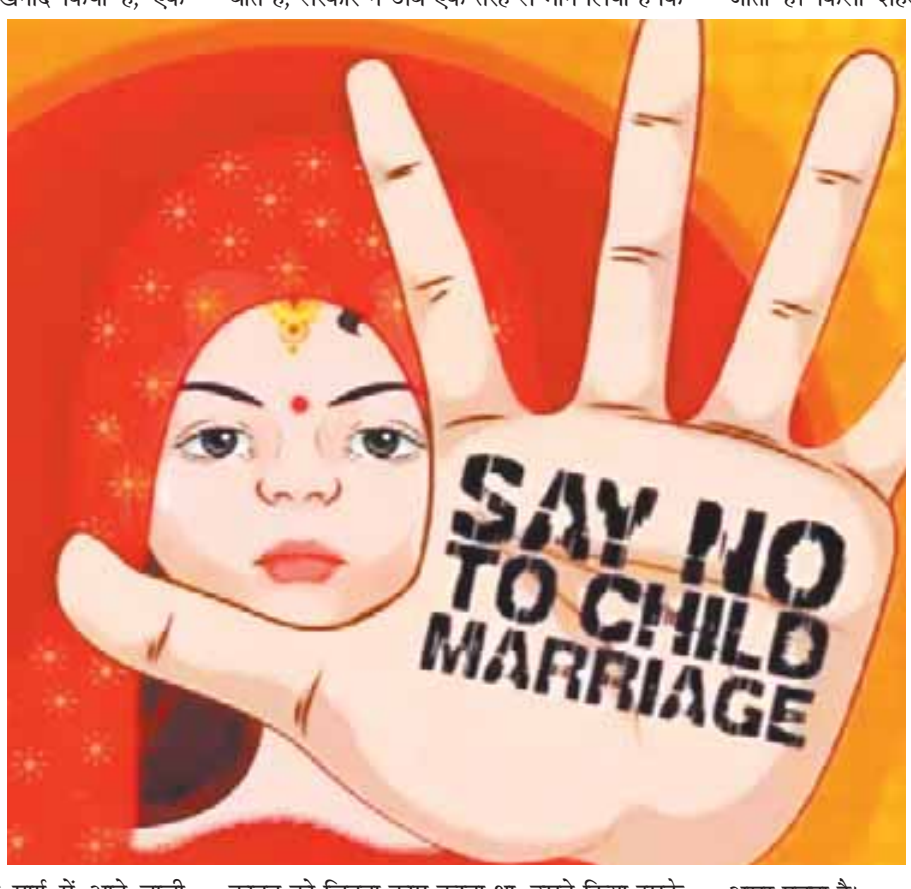


सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि यह समय की मांग है कि इस कानून को लागू करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। इस बाबत उन समुदायों व धर्मों के लोगों को बताया जाना चाहिए कि बाल विवाह कराया जाना एक आत्मघाती कदम है। यह समझना कठिन नहीं है कि कम उम्र में विवाह कालांतर जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य के लिये भी घातक साबित होता है। उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती और वे अपनी आकांक्षाओं का कैरियर भी नहीं बना सकते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कथन इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। केंद्रीय मंत्री ने उचित ही कहा है कि बाल विवाह मानवधिकारों का उल्लंघन और कानून के तहत अपराध है। अच्छी बात है, सरकार ने अब एक तरह से मान लिया है कि कानून को जितना काम करना था, उसने किया इसके आगे अब विशेष अभियान की जरूरत है। बाल विवाह को रोकने के लिए अकेले कानून के भरोसे न बैठते हुए ठोस जागृति-अभियान की अपेक्षा है। अब सरकार ने इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिये कमर कसी है, तो उसका स्वागत होना चाहिए एवं इस अभियान को व्यापक रूप देना चाहिए।

बाल विवाह की कुरीति को देश में व्यापकता से देखने को मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे खराब स्वरूप है। ठोस प्रयासों के बावजूद आज भी लगभग पांच में से एक लड़की का विवाह विधि सम्मत आयु 18 वर्ष से पहले कर दिया जाता है। किसी शहर में अगर एक विवाह सत्र में 1000 शादियां होती हैं, तो उनमें से 200 शादियों में दुल्हन की उम्र शादी लायक वैध नहीं होती। बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को यह भी बताया कि पिछले एक साल में लगभग दो लाख बाल विवाह रोके गए हैं। मतलब, सामाजिक संस्थाएं और पुलिस काम तो कर रही हैं, पर मंजिल अभी दूर है। बाल विवाह की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, असम और आंध्रप्रदेश में है। देश में 300 ऐसे जिले हैं, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है, लोग बेटियों का जीवन तो बचा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा भी देने लगे हैं, पर उन्हें अधिक पढ़ाने और आगे बढ़ाने पर उनका ध्यान नहीं है। बेटियों की जब कम उम्र में शादी होती हैं तो श्रम बल के रूप में न केवल उनकी उत्पादकता, बल्कि देश की क्षमता पर भी असर पड़ता है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' की भविष्य दृष्टि से प्रेरित नये समाज की संरचना का दूरगामी प्रकल्प है। बच्चों पर बाल विवाह थोपना उनके अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का भी दमन है। भले ही मजबूरी में वे इस थोपे हुए विवाह के लिये राजी हो जाएं, लेकिन उसकी कसक जीवन पर्यंत बनी रहती है। जो उनके स्वाभाविक विकास में एक बड़ी बाधा बन जाता है। निश्चय ही इस बाबत बदलाव लाने के लिये कानून में जरूरी बदलाव लाने के साथ ही समाज में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। इन सब दृष्टियों से यह अभियान सदियों से चली आ रही इस त्रासद परम्परा से मुक्ति का माध्यम बनेगा। पढ़ी-लिखी लड़की अगर विवाह-योग्य उम्र से ब्याही जाए, तो वह परिवार और समाज के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। कम उम्र में विवाह से न केवल संतानों की गुणवत्ता बल्कि परिवार की आर्थिक, सामाजिक और मनावैज्ञानिक क्षमता पर भी असर पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बाल विवाह दर में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक गिरावट दक्षिण एशियाई देशों में देखी गई है, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए अभियान के अंतर्गत इस परम्परागत विसंगति एवं विडम्बना को दूर करने के लिये व्यापक प्रयत्न किये जायेंगे। प्रारंभिक कार्ययोजना के अन्तर्गत बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के जरिये बाल विवाह के विरोध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी, बाल विवाह की शिकायत भी यहां दर्ज कराई जा सकती है एवं कार्य प्रगति की निगरानी भी की जाएगी। इस पोर्टल को सही ढंग से चलाया गया, गांवों और पंचायतों से जोड़ लिया गया, तो इसके सकारात्मक परिणाम आ सकते है। बाल विवाह मुक्त अभियान देश भर में युवा लड़कियों के सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। यह प्रगतिशील और समतापूर्ण समाज सुनिश्चित कर हर बच्चे की क्षमता को पूर्णता से साकार करेगा। इस अभियान का संदेश 25 करोड़ नागरिकों तक पहुंचने की उम्मीद है। यह निर्विवाद है कि देश को विकसित बनाने के लिए महिलाओं की पूरी शक्ति का उपयोग जरूरी है और महिला शक्ति बढ़ाने के लिए बाल विवाह को रोकना ही होगा। आज सामाजिक सोच एवं ढांचे में परिवर्तन लाने की शुरुआत हो गयी है, इसमें सृजनशील सामाजिक संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण होगा। आवश्यकता है वे अपने सम्पूर्ण दायित्व के साथ आगे आये। अंधेरे को कोसने से बेहतर है, हम एक मोमबत्ती जलाएं।

## कलेक्टर ने जिला स्तरीय समन्वयक समिति की बैठक में की स्वरोजगार मूलक योजनाओं की समीक्षा

**बैतूल।** कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समन्वयक समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की स्वरोजगार मूलक योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैंकों से समन्वय कर स्वरोजगार मूलक योजनाओं में शत प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत किए जाए। बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध कम प्रगति मिलने पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी सीएमओ को शोकाज नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य में प्रगति नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मकसूद अहमद, एलडीएम आशुतोष सिंह, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शिल्पा जैन, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक रोहित डावर सहित बैंक के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने डॉ.भीमराव अंबेडकर योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री उदयम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने किसान क्रेडिट कार्ड वितरण की समीक्षा कर आगामी दो दिनों में शत प्रतिशत कार्ड वितरण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

## सीएमओ ने कहा- मृतक की शॉट पीएम में टीबी रोगग्रस्त होने से फेफड़ों में पानी भरा पाया

### मामला बुधवार गंज क्षेत्र में मिले युवक के शव का

**बैतूल।** बुधवार को गंज क्षेत्र में दुकानों के सामने युवक का शव मिला था। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि युवक की मौत ठंड की ठिठुरन की वजह से हुई है, लेकिन नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आने पर मौके स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण व जांच में पाया गया कि मृतक बाबू धुर्वे पिता छत्रपाल निवासी चुन्नीदाना लोहिया वार्ड गंज बैतूल द्वारा प्रतिदिन हम्माल का कार्य किया जाता था। रात्रिकालीन विश्राम हिरानी मोबाइल के पास गलियारें में करता था। जिसकी मृत्यु सुबह 6.00 बजे के लगभग होना ज्ञात हुआ। मृतक के शॉट पीएम रिपोर्ट में टीबी रोगग्रस्त होने से दोनों फेफड़ों में पानी भरा पाया गया। जिसकी वास्तविक जानकारी के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल एवं सिविल सर्जन बैतूल से दूरभाष पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान उनके द्वारा मृतक बाबू धुर्वे वल्द छत्रपाल की मौत का कारण टीबी रोग से होना अवगत कराया। सीएमओ मटसेनिया ने बताया कि शीतकालीन को मद्दे नजर रखते हुए समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा नगरीय क्षेत्रों में बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, अस्पताल परिसर, एवं अन्य आवश्यक सार्वजनिक स्थानों पर जहां लोगों का आना-जाना व रुकना ठहरना, नगरपालिका आश्रय स्थल सहित स्थानों पर ठंड से बचाव के लिए प्रतिदिन अलाव की व्यवस्था की जा रही है। नगरपालिका आश्रय स्थल में प्रतिदिन 20-25 बेसहारा लोगों के लिए ठंड से बचाव के लिए व्यवस्था की गई हैं। नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में बेसहारा घूम रहे, ऐसे आश्रय लोगों को निकाय के आश्रय स्थल तक पहुँचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की हैं। जिन्हे एकत्रित करके आश्रय स्थल पर सुरक्षित रूप से वाहन के माध्यम पहुंचाया जा रहा है।

## जमीनी विवाद को लेकर आदिवासी युवक का किया अपहरण

### कमरे में बंद कर पीटा, पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार, एक फरार

**बैतूल।** जमीनी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा आदिवासी युवक का अपहरण करने और उसे कमरे में बंद कर रात भर पीटने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन्हें न्यायालय में पेश किया, वहीं एक आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। घटना बैतूलबाजार थाना क्षेत्र की है। बैतूलबाजार टीआई अंजना धुर्वे ने बताया कि आदिवासी युवक शिवदीन उर्फ गुड्डू लोखण्डे (38) पिपला के अपहरण और मारपीट की शिकायत परिजनों ने बैतूलबाजार थाने में 26 नवम्बर की सुबह की गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। घटना की जांच बैतूल एसडीओपी शालिनी परस्ते के द्वारा की जा रही है। टीआई अंजना धुर्वे ने बताया कि पिपला गांव में पीड़ित शिवदीन उर्फ गुड्डू लोखण्डे और आरोपी अशोक दाते, दादा उर्फ मोहित दाते, विक्की उर्फ आयुष दाते आपस में पड़ोसी हैं। पीड़ित सरकारी जमीन पर रहता है और आरोपी की खुद की जमीन है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में हमेशा विवाद होते रहता है। इसके अलावा रास्ते को लेकर भी विवाद होता है। 25 नवम्बर की रात दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने अपने भांजे छोटू उर्फ चंद्रकिशोर जो कि बैतूल रहता है उसे बुलाया था। चारों ने पीड़ित के घर में घुसकर उसके साथ, उसकी माँ और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। बाद में पीड़ित को घर से उठाकर अपनी कार से बैतूलबाजार थाने लेकर आए थे। पीड़ित को बाहर खड़ा करके आरोपियों ने बैतूलबाजार थाने में विवाद का आवेदन दिया था। जांच में पता चला कि पीड़ित को दभेरी गांव लेकर गए, वहां उसे एक कमरे में बंद करके उसके साथ जमकर मारपीट की गई। गला दबाने की भी काशिश की गई। गले पर निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि रात भर बंद रखने के बाद सुबह जब पीड़ित की हालत गंभीर हो गई तो उसे इलाज के लिए इटारसी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मामले को संदिग्ध होने पर इलाज से मना कर दिया। इसके बाद बैतूल वापस लाए। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट, अपहरण और एससी, एसटी एक्ट का मामला दर्ज किया है।

## घोड़ाडोंगरी की सड़कों का कायाकल्प शुरू, डामरीकरण से बदलेगा शहर का स्वरूप

**बैतूल।** मध्यप्रदेश शासन की महत्त्वाकांक्षी कायाकल्प योजना के दूसरे चरण की शुरुआत घोड़ाडोंगरी नगर में धूमधाम से हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष मीरावंती उइके, उपाध्यक्ष हरप्रीत सोनू खनूजा, सभापति सोना राजपूत, कविता महाले और योगेश कवडे द्वारा नारियल फोडक़र और विधिवत पूजा-पाठ कर किया गया। डामरीकरण का कार्य मेन रोड से शुरू होकर जनपद पंचायत से पिपरी की ओर जाएगा। नगर परिषद के इंजीनियर पंकज धुर्वे ने जानकारी दी कि पीआईसी के प्रस्ताव के अनुसार नगर की सात प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 65 लाख रुपए की लागत आएगी। नगर में हो रहे इन विकास कार्यों से जनता में उत्साह का माहौल है।

### मंडी में पिछले साल की तुलना में दोगुना मक्के की आवक, 32 साल में भी नहीं हुआ मंडी का विस्तार

# क्षमता- 12 से 15 हजार, आवक 25 से 30 हजार क्विंटल

# प्रभावित हो रही मंडी की व्यवस्थाएं

**संजय द्विवेदी, बैतूल।** जिले में पिछले कुछ दिनों से मक्के की बंपर आवक हो रही है। आवक इतनी अधिक हो रही है कि मंडी में उपज डालने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है। पिछले एक माह से मंडी में मक्के की आवक सबसे अधिक है। इस साल पिछले 9 दिनों में ही दो लाख से अधिक उपज की नीलामी मंडी में हो चुकी है। अभी कुछ दिनों से मक्के के दाम लगभग दो हजार के आसपास चल रहे है, जबकि इससे पहले 22 से 23 सौ रुपये मक्का बिक रहा था। तब मक्के की आवक थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन अब कृषि मंडी में मक्के की आवक बढ़ गई है। प्रतिदिन लगभग 15 से 20 हजार क्विंटल मक्का बेचने के लिए आ रही है। जिससे मंडी में शेड के भीतर उपज डालने के लिए किसानों को जगह नहीं मिल पा रही है। आवक इतनी अधिक है कि शेड कम पड़ जा रहे है। कुछ शेड में उपज के बोरे पड़े रहते है। बोरे हटाने की गति बहुत धीमी रहती है। समय पर परिवहन नहीं किया जाता है। जिसके कारण मंडी खाली नहीं होती है और किसानों को परेशान होना पड़ता है।

**बढ़ी आवक, मंडी का विस्तार नहीं-** सोयाबीन का उत्पादन कम होने और लगातार फसल खराब होने के कारण किसानों का रूख मक्का की तरफ बढ़ा है। इस साल जिले में मक्का की बंपर

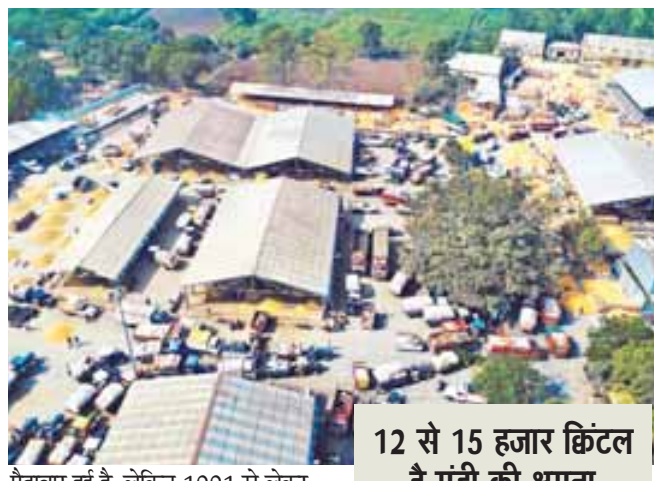

पैदावार हुई है, लेकिन 1991 से लेकर अब तक करीब 32 साल में मंडी परिसर का विस्तार नहीं हुआ। उल्टा कृषि उपज मंडी की 3 एकड़ जमीन पर सब्जी मंडी शुरू कर दी गई। जिससे 15 एकड़ से घटकर मंडी परिसर 12 एकड़ ही बचा। इसमें भी किसान विश्राम गृह, भोजन शाला, गोदाम सहित अन्य भवनों का निर्माण होने से मंडी परिसर में जगह कम होते जा रही है जबकि आवक लगातार बढ़ रही है। सीजन में आवक बढ़कर 25 से 30 हजार क्विंटल तक हो जाती है। जिससे मंडी के शेड तो दूर पूरा परिसर अनाज से भर जाता है। जानकारों की माने, तो जिले में सिंचाई की सुविधा बढ़ने से बोवनी का रकबा और उत्पादन बढ़ा है।

### 12 से 15 हजार क्विंटल है मंडी की क्षमता

कृषि उपज मंडी बडोरा की क्षमता 12 से 15 हजार क्विंटल की है। यहां अनाज रखने के लिए 21 शेड भी बने है। यहां इतनी आवक होने पर व्यवस्थाओं पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन इससे अधिक आवक होती है तो मंडी में अव्यवस्थाएं फैल जाती है। बता दे कि जिले में फसलों की बुवाई का रकबा लगभग हर साल बढ़ रहा है। जिससे मंडी में उपज की आवक भी 5 से 6 गुना बढ़ गई है। मंडी का विस्तार नहीं होने से अनाज डालने जगह ही नहीं बच पा रही है। परिणाम किसान और व्यापारी दोनों परेशान होते है और मंडी प्रबंधन को भी व्यवस्था बनाने में दिक्कते आती है, लेकिन अनाज की नीलामी करने मजबूर होना पड़ रहा है।

### ब्लॉकों की मंडियां बनी शोपीस

बैतूल के अलावा मुलताई, शाहपुर, भैंसदेही और आमला में कृषि मंडी है, लेकिन यह मंडियां केवल शोपीस बनी है। इन मंडियों में बहुत कम किसान उपज लेकर पहुंचते है। अधिकतर किसान उपज लेकर बैतूल मंडी लेकर आते है। कई किसानों का कहना है ब्लाक स्तर की मंडी और जिला मुख्यालय की मंडी के दामों में अंतर रहता है, इसलिए वे बैतूल उपज लेकर आते है। कई बार इतने अधिक किसान उपज लेकर पहुंच जाते है कि कृषि मंडी के सामने जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। मंडी परिसर में वाहनों की पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है। इससे किसान मंडी परिसर के बाहर ही वाहन खड़ा कर देते है। सुबह से बडोरा मंडी के सामने वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है। वाहनों की कतार के कारण जाम लग जाता है और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंडी परिसर में वाहनों की पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है।

**इस साल मक्के की रही दुगुनी आवक-** इस साल कृषि मंडी में मक्के की आवक पिछले साल की तुलना में दोगुनी रही है। कृषि उपज मंडी सचिव से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 2023 में अक्टूबर में 90,155.90 क्विंटल और नवंबर माह में 301178.40 क्विंटल कुल 3,91,334.3 क्विंटल मक्के की आवक हुई थी, जबकि इस साल 2024 में अक्टूबर माह में ही 1,47,696.80 क्विंटल और नवंबर माह में 4,79,736.60 क्विंटल कुल 6,27,433.40 क्विंटल के लगभग आवक हो चुकी है। अभी भी मंडी में मक्के की आवक बनी हुई है। 28 नवंबर को भी 24074 क्विंटल मक्के की आवक रही। मक्के की आवक बढ़ने से आज 29 नवंबर को मंडी में केवल मक्के की नीलामी बंद रहेगी। शेष उपज (जींस) की नीलामी होगी।

**कृषि उपज मंडी में कुल उपज की आवक**

| तिथि | उपज की आवक |
|---|---|
| 18 नवंबर | 29,090 क्विंटल |
| 19 नवंबर | 35,524 क्विंटल |
| 20 नवंबर | 27,728 क्विंटल |
| 21 नवंबर | 25,123 क्विंटल |
| 22 नवंबर | 26,414 क्विंटल |
| 25 नवंबर | 29,903 क्विंटल |
| 26 नवंबर | 26,472 क्विंटल |
| 27 नवंबर | 18,680 क्विंटल |
| 28 नवंबर | 27,587 क्विंटल |

### इनका कहना है -

मंडी की क्षमता कम है और आवक अधिक हो रही है। लेकिन मंडी के विस्तार के लिए आसपास जगह नहीं है। जगह होती तो अधिग्रहित कर मंडी का विस्तार कर सकते थे। मंडी में अभी क्षमता से 3 से 4 गुना तक आवक बढ़ गई है। जिसके कारण व्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि किसानों को दिक्कते न उठानी पड़े।

**- शीला खातरकर,**
मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी बडोरा

## पेड़ पर चढ़ा भालू, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा वन विभाग

**बैतूल।** एक भालू घर के सामने लगे पेड़ पर चढ़ गया। जिससे गांव में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के अमले को दी। सूचना मिलने के बाद अमला मौके पर पहुंचा और भालू को पेड़ से नीचे उतारने का रेस्क्यू शुरू किया। दरअसल चोपना क्षेत्र के लक्खीपुर गांव में बुधवार देर रात भालू गांव के बीच स्थित एक घर के आंगन में लगे पेड़ पर चढ़ गया। भालू को

देखकर गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने भालू को परेशान करने के बजाय शांत रखा और गुरुवार सुबह वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को सुरक्षित उतारने का प्रयास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा होने से रेस्क्यू टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वन विभाग ने इस घटना के बाद ग्रामीणों को सतर्क रहने और किसी भी जंगली जानवर को देखने पर तुरंत सूचना देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

# जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए चलाया जागरूकता अभियान

### हम होंगे कामयाब अभियान से गांव-गांव तक पहुंचेगी जागरूकता की अलख

**बैतूल।** ढोडरामोबाड़ में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'हम होंगे कामयाब' जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था प्रत्याशा एवं जिला पुलिस प्रशासन (महिला बाल विकास), जिला बैतूल द्वारा संयुक्त रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। सुरक्षित नारी, सशक्त समाज पखवाड़े के अंतर्गत 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा, बाल विवाह और अन्य प्रकार के अत्याचारों से बचाना है। थाना प्रभारी साईंखेड़ा थाना के राजन उईके ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि घरेलू हिंसा का सामना करना पड़े तो चुप न रहें, बल्कि पुलिस की मदद लें। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया और आश्वासन दिया कि पुलिस हर समय उनकी सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने यह भी कहा कि

यदि महिलाएं थाने नहीं आ सकतीं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी सूचना दे सकती हैं।

**शिक्षा और रोजगार पर दिया जोर-** प्रत्याशा संस्था की अध्यक्ष तूलिका पचौरी ने कहा कि बालिकाओं को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपनी बच्चियों की सुरक्षा के साथ उनकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दें। निमिषा शुक्ला ने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए कहा कि कम उम्र में विवाह से बालिकाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रमिला धोत्रे ने महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया और पलायन करने वालों की जानकारी सरपंच को देने की सलाह दी।

# अब कम दामों में मिलेगी रेत, मकान बनाना होगा आसान

### खनिज अधिकारी की मध्यस्थता के बाद सुलझा मतभेद

**बैतूल।** शहरवासियों के लिए यह अच्छी खबर है कि अब उन्हें रेत के अधिक दाम नहीं चुकाने पड़ेंगे। यह कवायद पिछले दिनों डंपर यूनियन की नाराजगी सामने आने के बाद विधायक के निर्देश पर खनिज अधिकारी ने डंपर-रेत ठेकेदारों की बैठक में सहमति बनने के बाद डंपर यूनियन ने रेत के

दामों में कमी कर दी है। अब रेत का डंपर 25 हजार के बजाए 21-22 हजार रूपये में मिलेगा। इससे मकान बनाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल बैतूल में रेत ठेकेदार और डंपर यूनियन के बीच पिछले कई दिनों से मतभेद चल रहे हैं। रेत ठेकेदार द्वारा दाम बढ़ाए जाने के बाद डंपर संचालकों को रेत परिवहन में काफी दिक्कतें हो रही थी। रेत के दाम बढने की ही वजह थी कि कई लोग अभी मकान बनाने के बावजूद रेत परिवहन नहीं कर रहे थे। इससे डंपर संचालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। यूनियन ने विधायक हेमंत खंडेलवाल से मिलकर रेत ठेकेदार द्वारा रेत के दाम बढ़ाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सभी ने समस्या का निराकरण नहीं होने पर हड़ताल पर भी जाने की चेतावनी दी थी। जिसके बाद विधायक के निर्देश पर खनिज अधिकारी ने डंपर संचालक और रेत ठेकेदार की बैठक लेकर सहमति बनाई। अब डंपर संचालकों को नदियों एवं स्टॉक रेत लेने पर 3 रूपये प्रति घनफीट कम दाम देना पड़ेगा। सूत्र बताते हैं कि डंपर यूनियन की समस्या देखते हुए खनिज अधिकारी मनीष पालेवार से चर्चा कर बीच का रास्ता निकालने के निर्देश दिए। पिछले दिनों पालेवार ने ठेकेदार के मैनेजर सतीष जादौन के साथ अपने कार्यालय में बैठक की। बैठक में डंपर यूनियन के सभी लोगों को बुलाया। सौहाद्रपूर्ण माहौल में बैठक के बाद डंपर यूनियन ने अपनी हड़ताल भी स्थगित कर दी है।

### इनका कहना है

रेत ठेकेदार और डंपर यूनियन के बीच दाम को लेकर कुछ मतभेद थे। बैठक करवाकर आपसी तालमेल बना लिया है। अब रेत के दाम कम करने का निर्णय लिया गया है।

**- मनीष पालेवार,**
उपसंचालक खनिज विभाग, बैतूल

रेत ठेकेदार रेत के लगातार दाम बढ़ा रहे थे। इससे डंपर यूनियन को नुकसान हो रहा था। हमने हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम देकर विधायक से मुलाकात की थी। इसके बाद खनिज अधिकारी के साथ बैठक हुई, तो ठेकेदार ने रेत के दाम कम कर दिए है, इसलिए हड़ताल रद्द कर दी है।

**- राजकुमार दीवान** अध्यक्ष डंपर यूनियन बैतूल

## परमार्थ के लिए कार्य करना ही सच्चा सामाजिक कार्य

### सावंगी में जल संरक्षण के संकल्प के साथ किया बोरी बंधान

**बैतूल।** जल संकट के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड आठनेर के निर्देशन में जल संरक्षण को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम सावंगी में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सेक्टर आठनेर के परामर्शदाता गोवर्धन राने ने अपना जन्मदिन बोरी बंधान कर मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, चराचर जगत में प्रत्येक प्राणी को जल की आवश्यकता होती है। यदि हम इस अमूल्य जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? परमार्थ के लिए निस्वार्थ कार्य करना ही सच्चा समाज कार्य है। मेंटर आशुतोष सिंह चौहान ने कहा कि जल संकट का भयावह रूप भविष्य में देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा, बिन पानी सब सून की पंक्ति आज के समय में पूरी तरह सटीक है। हमें जल संरक्षण के महत्व को समझकर समाज में जनजागरूकता लाने का प्रयास करना होगा। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने जल संरक्षण के संकल्प के साथ इस संदेश

को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था बोरपानी के अध्यक्ष राजू सलाम, सावंगी के अध्यक्ष दिनेश माकोड़े, मेंटर दिनेश साकरे, रघुनाथ दवडे, रमेश दवडे, हनुमंत राने, आकाश पाटिल, हेमलता दवडे, अश्विनी माकोड़े, प्रतीक घोरसे, जयश्री देशमुख सहित बड़ी संख्या में प्रस्फुटन समिति सदस्य और मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम (सीएमसीएलडीपी) के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

**जल संरक्षण के लिए जनजागरूकता का आह्वान-** कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया। मेंटर आशुतोष सिंह चौहान ने कहा कि जल संकट से बचने के लिए हमें तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे। अगर हम अभी नहीं संभले, तो भविष्य में भीषण जल संकट झेलना पड़ेगा। कार्यक्रम का समापन जल संरक्षण के संकल्प और भोजन प्रसादी के साथ हुआ। सभी उपस्थित लोगों ने जल संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया और समाज में जागरूकता फैलाने का वचन दिया। गोवर्धन राने का यह जन्मदिन समाज सेवा और परमार्थ का अनुपम उदाहरण बन गया।

## नपा सीएमओ ने किया नगर का भ्रमण

**बैतूल।** इंदिरा वार्ड स्थित एमपीईबी कार्यालय में जल निकासी की समस्या को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने एमपीईबी के कार्यपालन यंत्री एवं जुनियर इंजीनियर के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। समस्या स्थल पर जल निकासी के लिए एमपीईबी स्वयं के विंग द्वारा नाली बनाई जाकर समस्या का समाधान किए जाने का निर्णय लिया गया। भ्रमण के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने भूतपूर्व सैनिक संगठन के साथ बैठक कर निकाय के उपयंत्री विजय मछार को कारगील चौक पर रेलिंग लगाए जाने के निर्देश दिए गए।

## विनोद नागर को जलगांव में मिलेगा प्रेरणा सम्मान

**भोपाल।** राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, समीक्षक और स्तंभकार विनोद नागर को महाराष्ट्र की हिन्दी साहित्य गंगा संस्था ने

वर्ष 2024 का प्रेरणा सम्मान देने की घोषणा की है। यह सम्मान उन्हें 1 दिसंबर को जलगांव में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय हिन्दी साहित्य गंगा महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। संस्था की अध्यक्ष डॉ. प्रियंका सोनी 'प्रीत' के अनुसार नागर का चयन उनके छह खण्डों वाले रचना समग्र की पुस्तक 'छपा अनछपा' के लिए किया गया है। नागर को हाल ही में अमरावती की अखिल हिन्दी साहित्य सभा, जबलपुर की कादंबरी साहित्यिक संस्था और भोपाल की तुलसी साहित्य अकादमी ने भी सम्मानित किया है।

## एम्स भोपाल को एनीमिया पर अनुसंधान के लिए आईसीएमआर से 4.4 करोड़ रुपये का अनुदान

**भोपाल।** एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में, संस्थान अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रो. सिंह के मार्गदर्शन में संकाय सदस्य न केवल शोध में उत्कृष्टता हासिल कर रहे हैं, बल्कि समाज और स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने वाले विचारों को आकार दे रहे हैं। हाल ही में, एम्स भोपाल को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) से बहु-राज्यीय अनुसंधान अध्ययन के लिए 4.4 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसका उद्देश्य एनीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का समाधान करना है। इस शोध के महत्व को बताते हुए प्रो. सिंह ने कहा, एनीमिया भारत की एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है, जो खासकर महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करती है। एम्स भोपाल का यह अनुसंधान न केवल एनीमिया मुक्त भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा, बल्कि इसके समाधान के लिए एक प्रभावी और व्यापक मॉडल भी तैयार करेगा।

यह परियोजना, प्रो. सिंह के मार्गदर्शन में डॉ. पंकज प्रसाद, डॉ. दीप्ति डाबर, डॉ. सीमा महंत, डॉ. ई. जयशंकर और डॉ. अनिंदो मजूमदार द्वारा संचालित की जाएगी। वे अन्य राज्य और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर एनीमिया और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। यह परियोजना मौजूदा सरकारी पहलों को मजबूत करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश में कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार करेगी।

## नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 10 हजार अर्थदण्ड

**सुबह सवेरे सोहागपुर।**

विशेष न्यायालय पास्को एक्ट माननीय न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे सोहागपुर की अदालत ने आरोपी नीरज पिता ब्रजेश परसाई, उम्र-28 वर्ष, थानासोहागपुर को धारा-366 भारतीय दंड.विधान में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(ठ) 6 में 20 वर्ष, 5(अ) 6 में 20 वर्ष एवं 5(झ) 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 दस रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने घटना का संक्षिप्त विवरण में बताया कि दिनांक 22 सितम्बर.2021 को नाबालिग अभियोक्त्री के पिता ने थाना सोहागपुर में रिपोर्ट दर्ज करायी और बताया कि परिवार के सभी लोग रात को 10-11 बजे खाना खाकर सो गये थे। नाबालिग अभियोक्त्री भी अपनी मां के बाजू में सो गयी थी। वह करीब 3 बजे उठा तो देखा कि उसकी पत्नि के बाजू में नाबालिग अभियोक्त्री नहीं थी। उसने पत्नि को उठाया और आस-पड़ोस व रिश्तेदारों में पूछताछ की। लेकिन वह कहीं नहीं मिली। नाबालिग अभियोक्त्री को कोई बहला-फुसलाकर कहीं ले गया । इसकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की और नाबालिग अभियोक्त्री की तलाश की गयी। नाबालिग अभियोक्त्री को आरोपी नीरज परसाई पिता ब्रजेश परसाई अपने साथ बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले गया था । तथा उसकी इच्छा व सम्मति के बिना बार-बार बलात्संग किया। पुलिस थाना सोहागपुर ने संपूर्ण विवेचना पूर्ण करके अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। माननीय विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश सुरेशकुमार चौबे ने आरोपी नीरज पिता ब्रजेश परसाई को उक्त अपराध में दोषी पाकर 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बाबूलाल काकोड़िया एवं अपर लोक अभियोजक शंकरलाल मालवीय ने प्रकरण में संयुक्त रूप से सशक्त पैरवी की थी।

### एम्स भोपाल की डॉ. सीमा पी. महंत को

# 'सतत विकास लक्ष्यों के लिए तकनीकी, सामाजिक और प्रबंधन हस्तक्षेप' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के लिए सम्मान

**भोपाल।** एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, संस्थान ने स्वास्थ्य और अकादमिक क्षेत्र में नई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हाल ही में, एम्स भोपाल के मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉ. सीमा पी. महंत को 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड मैनेजमेंट इंटरवेंशन्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स' (एनडीआईएम , नई दिल्ली) मे'सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रो. सिंह ने डॉ. महंत को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा, हम एम्स भोपाल में स्वास्थ्य सेवा को नवाचार, शिक्षा और निवारक उपायों के माध्यम से बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीवनशैली में बदलाव इस मिशन का अहम हिस्सा है, जो दिखाता है कि छोटे बदलाव बड़े

परिणाम ला सकते हैं।

एम्स भोपाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने कई पहलें लागू की हैं, जैसे टेलीमेडिसिन, डॉक्टर-से-डॉक्टर संचार प्लेटफार्म, मोबाइल ऐप के जरिए स्वास्थ्य जांच और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी क्लिनिक, जो उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों का आकलन करने के लिए एक विशेष स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करता है।

'इलनेस टू वेलनेस' की अवधारणा को बढ़ावा देते हुए, एम्स भोपाल इस बात पर जोर देता है कि दैनिक दिनचर्या में छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बना सकते हैं। प्राकृतिक पोषण को अपनाना, नियमित शारीरिक व्यायाम करना, शराब और धूम्रपान से बचना, और शरीर के वजन, रक्त शर्करा, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल स्तर और कमर की माप जैसे स्वास्थ्य संकेतकों को संतुलित बनाए रखना जैसे सरल उपाय उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं, साथ ही मृत्यु दर को 25 प्रतिशत तक घटा सकते हैं।

## आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एम्स भोपाल को किया सम्मानित

**भोपाल।** एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, संस्थान को अपनी उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एनएचए ने देशभर में 100 मॉडल स्वास्थ्य संस्थानों की पहचान की है, जिसमें एम्स भोपाल को शीर्ष तीन स्वास्थ्य संस्थानों में स्थान प्राप्त हुआ है। इसी संदर्भ में, एनएचए ने 27 नवंबर 2024 को नॉएडा (उ.प्र.) में इन मॉडल संस्थानो की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में एबीडीएम के तहत विभिन्न एम्स/आईएनआई में डिजिटल स्वास्थ्य पहलों की प्रगति और क्रियान्वयन का गहन मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही, पिछले महीनों में एबीडीएम के अंतर्गत चिन्हित 100 मॉडल स्वास्थ्य संस्थानो का आकलन भी किया गया।

प्रो. सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय एबीडीएम से जुड़े सभी संकाय सदस्यों, अधिकारीयों एवं अन्य कर्मचारियों को दिया और कहा की वे एबीडीएम के सभी मानकों को रोगियों के सर्वोत्तम हित में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएचए के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। कार्यशाला के दौरान एनएचए ने एम्स भोपाल के समर्पित प्रयासों को एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और उत्कृष्ट कार्यों के लिए एम्स भोपाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

## पेरिस में पूर्व विधायक स्व. दीवान के पोत्र वैभव सम्मानित

**सुबह सवेरे**

**सोहागपुर।** पेरिस में पूर्व विधायक स्व. विनय कुमार दीवान के पोत्र , पूर्व विधायक सविता दीवान के भतीजे एवं विवेक दीवान के पुत्र वैभव दीवान को पेरिस में इस वर्ष के यूरोप रीजन बिजनेस एलिट 40 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त अवार्ड सभी क्षेत्रों में से 40 वर्ष के यंग लीडर को दिया जाता है ।जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। पूरे विश्व में 200 यंग लेटर को यह अवार्ड मिलता है । जिसमें यूरोप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आदि शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि वैभव ग्राम मारागांव तहसील माखननगर जिला नर्मदापुरम के निवासी हैं।

### प्रारंभिक बाल्य विकास पर शोध के लिए एम्स भोपाल को आईसीएमआर का 2.5 करोड़ अनुदान

**भोपाल।** एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में संस्थान लगातार नवाचार, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी क्रम में, एम्स भोपाल को 'जोखिमग्रस्त' बच्चों में प्रारंभिक बाल्य विकास (ईसीडी) पर शोध के लिए आईसीएमआर इंटरमीडिएट ग्रांट से सम्मानित किया गया है। यह शोध परियोजना शुरुआती जैविक और मनोवैज्ञानिक अनुभवों का मस्तिष्क विकास पर प्रभाव समझने और इससे जुड़े समस्याओं का समाधान करने पर केंद्रित है। इस परियोजना में कुपोषण, आयरन और आयोडीन की कमी, संज्ञानात्मक उत्तेजना की कमी और मातृ अवसाद जैसे प्रमुख कारकों का अध्ययन किया जाएगा, जो बच्चों के विकास में बाधा बनते हैं।

## ताज्जुब, अतिक्रमण की जमीन से नर्मदा शिक्षा समिति का बोर्ड तक पुत गया..?

**नर्मदापुरम।** नगरपालिका की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए नर्मदा शिक्षा समिति का पूरा कारोबार रातोंरात हट गया..! अतिक्रमण की जगह से इस शिक्षा संस्थान के प्रचार प्रसार वाले बोर्ड बगैरह तक गायब हो गए, पोत दिए गए.. भला क्यों..? यह अब रहस्य है। पर सौ वर्ष से नगरपालिका के नाम पर दर्ज जमीन पर शिक्षाविद पंडित रामलाल शर्मा के उत्तराधिकारियों ने आज भी इस जगह अपने पिता के नाम पर स्कूल खोल अपना अतिक्रमण बरकरार रखा है ऐसा क्यों..? शायद उच्च न्यायालय में दायर नर्मदा शिक्षा समिति प्रबंधन के विरुद्ध फैसला आने से पहले कानूनी दांव-पेंच के तहत नर्मदा शिक्षा समिति का कारोबार रातोंरात समेटा गया है। वैसे तो इस समय तोड़ी गई बजरिया स्कूल का पूरा रकबा अतिक्रमण कारी नर्मदा शिक्षा समिति प्रबंधन के कब्जे में है। छह महीने हो चुके बजरिया स्कूल तोड़े हुए, और आडिटोरियम बनाने ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए देढ़ माह हो चले टीन की घेराबंदी कर आज दिनांक तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है । ऐसे में सवाल उठता है कि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त रसूखदार अतिक्रमण कारी जिसके विरुद्ध प्रशासन कारवाई करने में अक्षम और घुटने टेक है, फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने उच्च न्यायालय में गलत जानकारी देते हुए उनके पक्ष में लिखित बयान दिए है यदि बजरिया स्कूल की पूरी जमीन पर अतिक्रमण कर अपने चपेट में ले भी ले तो क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ पायेगा..?

## पुलिस ने फिर दो अपहृत नाबालिग को सकुशल ढूंढकर परिजन को सौंपा, अब तक अपहृत 251 में से 246 बालक-बालिकाओं को किया परिजन के सुपुर्द

**देवास/मोहन वर्मा।** देवास पुलिस अपराधों के खिलाफ दिनों ज़बरदस्त कार्यवाही कर रही है। थाना बैंक नोट प्रेस के द्वारा मात्र 12 घण्टे मे एक अपहृत नाबालिग बालिका को सकुशल ढूंढकर परिजनो के चेहरो पर मुस्कान लौटाई गई। इसी तरह औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक और बालक को भी ढूंढकर परिजनो को सौंपा गया।

'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा समस्त थानो को लंबे समय से अपहृत नाबालिक बालक/बालिका को मिशन स्तर पर कर्तव्यरीन रहकर ढूढने हेतु निर्देशित किया है । इसी क्रम मे थाना बैंक नोट प्रेस के अपराध क्रमांक 950/2024 धारा 137(2) BNS की नाबालिक बालिका विगत 12 घण्टों से लापता थी । जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन मे उप पुलिस अधीक्षक(एलआर) श्री संजय शर्मा के निर्देशन मे थाना प्रभारी बैंक नोट प्रेस श्री अमित सोलंकी के नेतृत्व मे पुलिस टीम लगातार मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यो के आधार पर कर्तव्यरथ थी । पुलिस को अहम सूचना प्राप्त हुई कि उक्त नाबालिक बालिका को देवास मे देखा गया है । जिस पर तत्काल पुलिस के द्वारा विशेष टीम को रवाना किया गया है । उक्त टीम के द्वारा नाबालिक बालिका को दिनांक 28.11.2024 को देवास से सकुशल ढूंढकर परिजनो के सुपुर्द किया गया। इसी तरह औद्योगिक थाना क्षेत्र से अपहृत एक और बालक को भी ढूंढकर परिजनो को सौंपा गया। प्रकरण मे नाबालिक बालिका/बालक द्वारा दिये गये पुलिस कथन एवं माननीय न्यायालय के समक्ष बतलाये गये साक्ष्यो के आधार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2024 में देवास पुलिस द्वारा कुल 251 अपहृत नाबालिक बालक/बालिकाओं के अपराध पंजीबद्ध किये जाकर उनमें से कुल 246 बालक/बालिकाओं को दस्तयाब किया गया।

पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसा करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दक्षता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

## अलसुबह फजर की नमाज से होगा इज्तिमा का आगाज

### 4 दिनों तक चलेगा मजहबी तकरीरों का दौर, जुमा की नमाज के बाद जुटेंगी सैकड़ों जमातें

**भोपाल।** दीनी समागम के लिये दुनियाभर में अपनी अलग पहचान रखने वाला राजधानी भोपाल में आयाजित आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज शुक्रवार अलसुबह फज्र की नमाज के बाद से शुरू होगा। चार दिन चलने वाले इस मजहबी समागम का समापन सोमवार को दुआ ए खास के साथ होगा। इन चार दिनों में दिल्ली मरकज समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आए उलेमा अपनी मजहबी

तकरीरें पेश कर लोगो को अपने रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की बात बतायेंगे। इज्तिमा के पहले दिन सादगी के साथ सैंकड़ों निकाह भी होंगे। इस समागम के समापन पर बड़ी तादाद में जमाते देश दुनिया के सफर पर रवाना होंगी। ईंटखेड़ी स्थित इज्तिमागाह पर बीते काफी समय से जारी तैयारियां पूरी हो गई है। स्थानीय वैलेंटियर और विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने लगातार प्रयास कर इज्तिमागाह को तैयार कर दिया है। इसमें शामिल होने गुरुवार दिन से ही जमातों के राजधानी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो था, जो देर रात तक जारी रहा। इसके साथ ही शुक्रवार सुबह फज्र की नमाज़ के बाद शुरू होने वाली तकरीर और बयान के दौर में शामिल होने के लिए अल सुबह भी बड़ी सख्या में लोग इज्तिमागाह पहुंचेंगे। यहाँ लगे पंडाल में लाखो लोगो के ठहरने का इंतेजाम किया गया है। इज्तिमागाह पर पिछले सालों के मुकाबले इस साल बढ़ी हुई तादाद में जमाते पहुंचने की उम्मीद है। जिसके चलते यहां लगे पंडाल के दायरे को बढ़ाते हुए लाखो जमातियों के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। वहीं जरूरत पढ़ने पर और पंडाल लगाए जाने की तैयारी भी रखी गई है। इज्तिमा में इस बाद बाइक एबुंलेस की व्यवस्था का भी इंतेजाम रखा गया है। आयोजको ने बताया की बताया कि इज्तिमा स्थल पर प्रशासन की और से मेडिकल कैंप बनाया गया है, जिसमें 24 घंटे डॉक्टर और आवश्यक मेडिकल सेवाएं मौजूद रहेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है, तो उसे प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस के साथ ही इस बार बाइक एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। बाइक एंबुलेंस में बीमार व्यक्ति को आराम से लेटा कर अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। आयोजन स्थल के चारो और के रूट पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है, जिसके चलते बाइक एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। दुनिया भर से आने वाली जमातों के खानपान के इंतजाम में बनाये गये फूड में रियायती दरों पर चाय, नाश्ता, खाना और पीने का पानी उपलब्ध रहेगा। नो लॉस नो प्रॉफिट की धारणा के साथ इज्तिमागाह पर कम पैसो में भरपेट खाना, नाश्ता और पानी की बॉटले और चाय उपलब्ध होगी।

### प्रदेशों के रहेंगे अलग अलग हलके

प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाली जमातों और स्थानीय जमातियों के लिए भी हलके तय कर दिए गए हैं। यहां आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बरार, नागपुर, गुजरात, मुंबई, वादी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नेपाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेवात, राजस्थान, दिल्ली आदि के खेमे तैयार किए गए हैं।

### गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

इज्तिमा इंतजामों में ईंटखेड़ी क्षेत्र के स्थानीय लोगों का बड़ा योगदान रहता है। इनमें बड़ी तादाद में हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी शामिल हैं। आने वाले मेहमानो के लिये यहाँ दी गई दुकानो में करीब 300 दुकानें हिंदू समुदाय के लोगों को भी आवंटित की गई हैं। इसके अलावा अलग अलग सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों में अन्य धर्म से जुड़े लोग हैं। जो इज्तिमा व्यवस्थाओं को सरकारी सेवा के साथ अतिरिक्त पुण्य के तौर पर अंजाम दे रहे हैं।

### ये हैं इंतेजाम

- इज्तिमा आयोजन में सैकड़ो सामूहिक निकाह आयोजन के पहले दिन होंगे।
- नहाने और वूजू के लिए गर्म पानी का इंतेजाम भी किया गया है, हजारो लीटर की पानी की टंकियों में पानी गर्म रहेगा।
- वॉलेटियर, रखेंगे सफाई का ख्याल, पंडाल में रहेगें डस्ट बीन।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से इज्तिमागाह को रखा जाएगा दुर्गंध रहित
- इज्तिमागाह पहुंच मार्ग पर वालेंटियर संभालेंगे यातायात व्यवस्था, पुलिस की रहेगी निगरानी
- ट्रैफिक सहित अन्य इंतजामों के लिए गुरुवार से ही वॉलेंटियर्स को तैनात कर दिया गया हैं।
- बाहर से आईं जमातों का गुरुवार सुबह से ही पहुंचने का सिलसिला शुरू, देर तक चलता रहा दौर, सैकड़ो जमाते शुक्रवार सुबह तक आमद देगी।

## केंद्रीय रेल मंत्री से सांसद आलोक शर्मा ने की भोपाल एक्सप्रेस के मथुरा स्टॉपेज की मांग

**भोपाल।** सांसद श्री आलोक शर्मा ने आज नई दिल्ली स्थित रेल भवन में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भेंटकर, रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज मथुरा स्टेशन किए जाने पर चर्चा की। भोपाल एक्सप्रेस का मथुरा स्टेशन पर स्टॉपेज हो जाने से भोपाल और इसके आसपास के नगरों से गिरिराज जी की परिक्रमा एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन की सुविधा सुलभ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर को महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा आयोजित मंडल परिक्षेत्र के सांसदगणों की बैठक में भी भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल एक्सप्रेस के मथुरा स्टॉपेज की मांग उठाई थी।

## दो दिवसीय जस्टिस मेकर्स मेला आज से

**भोपाल।** 'जस्टिसमेकर्स मेला' का आयोजन 29-30 नवम्बर 2024 को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित होगा। इस मेले में देश के 180 जिलों और 200 से अधिक संगठनों के 700 चेंजमेकर्स शामिल होंगे। यह मेला न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए विचारों और नेतृत्व का एक बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन होगा। इसमें चार मौजूदा न्यायाधीशों के साथ-साथ कई प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सोसायटी के नेता और उद्यमी शामिल होंगे, जो विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और परिवर्तन के रास्ते तलाशेंगे। जस्टिस मेकर्स मेला की आयोजन समिति से जुड़े सचिन मल्हान, आर्तिका राज, आर्थोंव बनर्जी ने बताया 'बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों का जुड़ना और मिलकर काम करना ज़रूरी है।' यह मेला ऐसा मंच बनेगा, जहाँ क़ानूनी इनोवेटर्स, तकनीकी विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ न्यायाधीश, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, कलाकार, सामुदायिक संगठनों के कार्यकर्ता, और युवा साथी एकसाथ आ पाएँगे। यहाँ लोग नए विचार और नए विधान देखेंगे - जानेंगे - समझेंगे और बदलाव लाने वाले प्रेरक लोगों से मि ल सकेंगे। इसके साथ ही, उन मुद्दों पर चर्चा भी कर सकेंगे जहाँशायद उनके आपसी विचार एक-दूसरे से मेल न खाते हों। यह मंच हमें सार्थक संवाद करने और न्याय से जुड़े समाधान मिलकर तलाशने का अवसर देगा।' उल्लेखनीय है कि यह 'जस्टिस मेकर्स मेला' पहले कुछ महानगरों में आयोजित हो चुका है। पहले के मेलों का आयोजन दिल्ली, बैंगलोर और पुणे में हुआ था।

# डिंडौरी में अधेड़ की लाश मिली..ठंड से मौत की आशंका

## एमपी में दिन का पारा 4.5 डिग्री लुढ़का, अगले 2-3 दिन में और बढ़ेगी ठंड

**भोपाल (नप्र)।** डिंडौरी में गुरुवार सुबह बस स्टैंड पर एक अधेड़ की मौत हो गई। ठंड के चलते उसकी मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। इससे पहले बुधवार को बैतूल में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदे में सो रहे युवक की अकड़ी हुई बॉडी मिली थी।

उत्तरी हवाओं की वजह से मध्यप्रदेश में रात और दिन लगातार ठंडे बने हुए हैं। खासकर पूर्वी हिस्से में दिन का टेम्प्रेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। बुधवार-गुरुवार की रात मंडला पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां रात का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का तापमान 7.2 डिग्री, टीकमगढ़ में 7.5 डिग्री, नौगांव में 8.6 डिग्री, मलाजखंड

में 9.3 डिग्री और रीवा में 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

**बड़े शहरों में जबलपुर सबसे ठंडा-** बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में रात का तापमान 10.2 डिग्री, इंदौर में 13.2 डिग्री, ग्वालियर में 10.9 डिग्री, उज्जैन में 12.2 डिग्री और जबलपुर में 9 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल में 6 दिन के बाद पारा 10 डिग्री के ऊपर पहुंचा। इससे पहले की छह रातों में पारा 8.8 डिग्री से 9.8 डिग्री के बीच रहा था। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार ने बताया-नवंबर के आखिरी सप्ताह में दिन-रात के टेम्प्रेचर में गिरावट होने का ट्रेंड है। इस बार भी ऐसा ही मौसम है। पश्चिम-उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन में वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव हो सकता है। जिससे बर्फीली हवा की रफ्तार तेज हो जाएगी और एमपी भी इसकी चपेट में आ जाएगा।

**260 किमी/घंटे की रफ्तार से चल रही जेट स्ट्रीम-** मौसम वैज्ञानिक कुमार ने बताया कि पश्चिम-उत्तर भारत के ऊपर जेट स्ट्रीट 260 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही है। लेकिन इसकी ऊंचाई 12.6 किमी है, इस वजह से प्रदेश में असर कम है। जब हवा नीचे बहेगी तो कड़ाके की ठंड होगी।

वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से दिसंबर के पहले सप्ताह में ही यह दौर शुरू हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फबारी हो रही है। इस वजह से जेट स्ट्रीम हवाओं की रफ्तार ज्यादा है।

### प्रदेश के पूर्वी हिस्से में दिन का पारा लुढ़का

बुधवार के दिन के तापमान की बात करें तो एमपी का पूर्वी हिस्सा ऐसा है, जहां तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। नरसिंहपुर में एक ही दिन में 4.5 डिग्री, मलाजखंड में 3.1 डिग्री, सीधी में 1.6 डिग्री, रीवा में 1.8 डिग्री, जबलपुर-नौगांव में 1 डिग्री तापमान गिरा।

पश्चिमी हिस्से के भोपाल, बैतूल, खंडवा, खरगोन, पचमढ़ी में भी पारा गिरा लेकिन धार, गुना, नर्मदापुरम, इंदौर, रायसेन, रतलाम, शिवपुरी और उज्जैन में मामूली बढ़ोतरी रही।

### भोपाल में पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

नवंबर में भोपाल में रात का तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। पिछले 10 साल से ऐसा ही ट्रेंड है। इस बार भी दूसरे सप्ताह से पारा तेजी से लुढ़क रहा है। यह 8.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो रिकॉर्ड है। मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल में नवंबर में रात का तापमान 6.1 डिग्री तक पहुंच चुका है। यह 30 नवंबर 1941 को दर्ज किया गया था। इस महीने बारिश होने का ट्रेंड भी है। 10 साल में दो बार बारिश हो चुकी है। साल 1936 में इस महीने में साढ़े 5 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है।

# मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया हेंडिल पर जारी संदेश में कहा कि महान संत, विचारक एवं समाजसेवी महात्मा फुले ने सारी जिन्दगी समाज के उपेक्षित, शोषित वर्ग के सम्मान, उत्थान एवं ईश्वर की इस कृति को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिये अनवरत कार्य करते रहे। वे सत्यशोधक समाज के प्रवर्तक थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नारी शिक्षा एवं वंचितों के लिए समर्पित, संत श्री ज्योतिबा फुले का जीवन हमारे लिए पथ प्रदर्शक प्रेरणादायी व सीखने वाला रहा है।

# चलती एंबुलेंस में नाबालिग से 3 बार रेप

## बहन बुलाकर ले गई, जीजा ने दुष्कर्म किया; चार आरोपियों में मामा भी शामिल

**मऊगंज (नप्र)।** मऊगंज में चलती एंबुलेंस में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पीड़िता के मामा के दामाद यानी जीजा पर है। वारदात 22 नवंबर को हनुमना थाना इलाके की है। नाबालिग ने 25 नवंबर को 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई। इनमें मामा, उसकी बेटी, दामाद और एंबुलेंस ड्राइवर शामिल हैं। 27 नवंबर को जीजा और एंबुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, मामा और उसकी बेटी की तलाश जारी है।

### एंबुलेंस में दोस्त, उसकी पत्नी को भी बैठा लिया

पुलिस के मुताबिक, 22 नवंबर को जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर पंडित को हनुमना थाना इलाके के लासा गांव से मरीज लेने के लिए कॉल आया। पंडित एंबुलेंस लेकर निकला तो उसका दोस्त राजेश केवट और उसकी पत्नी मंजू केवट भी साथ हो लिए। लासा गांव में ही मंजू का मायका है।

### बहन उतर गई, जीजा छेड़छाड़ करने लगा

पीड़िता ने एफआईआर में बताया- 22 नवंबर की शाम मामा रामायण केवट की छोटी बेटी मंजू मेरे पास आई और अपने घर चलने के लिए कहा। मैं उसके साथ चली गई। वहां एक एंबुलेंस खड़ी थी। इसमें मामा रामायण केवट, उनकी बड़ी बेटी मनीषा, दामाद राजेश और ड्राइवर पंडित बैठे थे।

मंजू ने अपनी दीदी मनीषा की ननद के घर घूमने जाने की बात कही। मैं तैयार हो गई। मैं और मंजू एंबुलेंस में पीछे की सीट पर बैठे जबकि जीजा राजेश और मामा रामायण ड्राइवर पंडित के पास आगे बैठ गए। थोड़ी दूर पहुंचकर मंजू पानी लेने की बात कहकर एंबुलेंस से उतर गई। जीजा राजेश पीछे आकर मेरे पास बैठ गए।

### जान से मारने की धमकी देकर 3 बार दुष्कर्म किया

ड्राइवर एंबुलेंस को पहाड़ी की तरफ ले गया। रातभर में राजेश ने मेरे साथ तीन बार दुष्कर्म किया। सुबह करीब 5 बजे तीनों मुझे घर के पास छोड़कर चले गए। मैंने अपनी मां को इस बारे में बताया, तब उन्होंने लोक-लाज के डर से चुप रहने को कहा। हिम्मत करके 25 नवंबर को थाने पहुंचकर एफआईआर कराई।

### मुख्य आरोपी और ड्राइवर गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

हनुमना थाना प्रभारी अनिल काकड़े ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर राजेश केवट और एंबुलेंस ड्राइवर पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। रामायण और मंजू की तलाश की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग पांडे ने कहा, वारदात में इस्तेमाल एंबुलेंस जब्त की गई है। फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

# मप्र में अब गेस्ट टीचर भी 'अतिशेष'

## डीईओ को निर्देश-अतिरिक्त गेस्ट टीचर को तुरंत रिलीव करो

**भोपाल (नप्र)।** स्कूल शिक्षा विभाग में रेग्युलर टीचर के बाद गेस्ट टीचर भी अतिशेष हो गए हैं। विभाग एक साल तक अतिशेष शिक्षकों की काउंसिलिंग कर दूसरे स्कूलों में पदस्थ करता रहा। अब जाकर पता चला कि गेस्ट टीचर भी अतिशेष हैं। जबकि इन्हें रिक्त पदों के विरुद्ध रखा जाता है।अब अपर संचालक लोक शिक्षण ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को लिखा है कि GFMS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करो। यानी इन शिक्षकों को अब तक मानदेय दिया जा रहा था। बता दें कि विभाग 9450 नए गेस्ट टीचर की भर्ती कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जर्मनी के म्यूनिख पहुंचने पर भारतीयों ने पारंपरिक रूप से आत्मीय स्वागत किया।

# मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन

## चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी रखने का विरोध

**भोपाल (नप्र)।** चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने के निर्णय के खिलाफ गुरुवार को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने भोपाल सहित प्रदेश के 53 जिला मुख्यालयों पर कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि सरकार ने अगले 5 साल में 2 लाख 50 हजार कर्मचारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसी में चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरने को कहा गया है।

संघ के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में सतपुड़ा भवन के सामने भोपाल में प्रदर्शन हुआ। जिसमें शर्मा ने आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी निजी एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ऐसी भर्ती के लिए एक एजेंसी तय की जाए और वेतन व्यवस्था के साथ नियम बनाए जाएं। वे कहते हैं कि विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थाईकर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं अंशकालीन कर्मचारी कार्यरत हैं। चतुर्थ श्रेणी के पद इन कर्मचारियों से भरे जाएं। उन्हें विभागों में

ही खाली चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया जा सकता है। इससे सरकार पर आर्थिक भार नहीं आएगा।

शर्मा ने बताया कि सरकार इस आदेश को निरस्त नहीं करती है तो आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सभी घटक संघ इसका विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो भोपाल में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद मंत्रालय जाकर प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदर्शन में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी, पेंशनर्स संघ के कार्यकारी अध्यक्ष एलएन कैलासिया, संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष भोपाल उमाशंकर तिवारी, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय मिश्रा एवं विजय रघुवंशी, पेंशनर संघ के उप प्रांताध्यक्ष अध्यक्ष अशोक मिश्रा, बालाघाट संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर भार्गव, उप प्रांताध्यक्ष अध्यक्ष कैलाश लाल, शिक्षा समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।

# मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद की फंडिंग रोकने में ईएजी ग्रुप की बैठक सिद्ध होंगी मील का पत्थर : राज्यपाल

## भारत सरकार टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्ती से कार्य कर रही है : केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री चौधरी

**भोपाल (नप्र)।** ईएजी (यूरेशियन ग्रुप) देशों की बैठक मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद की फंडिंग रोकने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। सभी बड़े देशों को एकजुट होकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एकजुट होकर बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। विश्व में आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए सभी ईएजी ग्रुप सदस्यों देशों का एकजुट होना बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इन्दौर में गुरूवार को 41वीं ईएजी प्लेनरी देशों की बैठक के उद्घाटन सत्र में माननीय राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कही।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि भारत में डिमॉनिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन से पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास हुए। उन्होंने कहा आधुनिक तकनीक के उपयोग से अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए और अधिक विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए ईएजी ग्रुप देश को मजबूत कूटनीतिक और सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए ईएजी ग्रुप देशों के प्रयास प्रभावी परिणामकारक सिद्ध होंगे।

कार्यक्रम को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री

पंकज चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा वित्त शोधन और आतंकवाद को वित्त पोषण की रोकथाम के लिए यूरेशियन देशो का ग्रुप महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा भारत सरकार टेरर फंडिंग के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। भारत में काला धन अधिनियम, आर्थिक अपराध को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए है और यह लगातार जारी हैं। भारत में साफ और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली के लिए जीएसटी, डिजिटल इंडिया के तहत विशेष प्रयास किए गए हैं। यूपीआई डिजिटल लेनदेन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। भारत में परिवर्तन निदेशालय लगातार सशक्त हो रहा है। भारत की सभी एजेंसियां द्वारा मिलकर आतंकवाद और उग्रवाद को धन पोषित करने वालों, मनी लांड्रिंग पर प्रभावी और कड़ी कार्रवाई हो रही हैं। भारत के इन प्रयासों को और सशक्त बनने में ईएजी ग्रुप की बैठक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की नगरी में ईएजी ग्रुप की बैठक गर्व का विषय हैं। उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग सीधे तौर पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, लेकिन जब यह आतंकवाद को पोषित करती है, तब विश्व शांति और सद्भाव के समक्ष गंभीर चुनौतियों को जन्म देती है। आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय मदद समस्त विश्व के लिए चिंता का सबब बनी हुई है इससे निपटने के लिए विश्व के बड़े देशों को एकजुट होना होगा। यह आयोजन वैश्विक अखंडता और मानवता के हित की दिशा में बड़ा कदम है।

### विजयपुर विधायक बोले-

# मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया

## टीआई-एसडीओपी ने धमकाया कि चुनाव मत लड़ना; नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा

**भोपाल (नप्र)।** विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और वन मंत्री रामनिवास रावत को हराकर विधायक बने कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बड़ा आरोप लगाया है। मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि विजयपुर से उम्मीदवारी के लिए जब मेरा नाम चल रहा था, तब मुझे धमकाया गया, मुझे लालच दिया गया।

कांग्रेस ने विधायक ने आरोप लगाया कि रामनिवास रावत के रिश्तेदार जो टीआई

है, एसडीओपी के साथ मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं तो तुम समझ सकते हो हम क्या कर सकते हैं। मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, कहा गया कि 2 करोड़ रुपए अभी ले लो, 3 बाद में ले लेना।

**डकैत बुलाकर मुझे मारने की कोशिश की गई-** विधायक मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि जब मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे मारने की कोशिश की गई। बीजेपी ने डकैतों को बुलाकर मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन मैं डरा नहीं और चुनाव लड़ा। पुलिस और अधिकारी सभी लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। बूथ पर बैठे हमारे एजेंटों तक को अगवा किया गया, नहीं तो हम 50 हजार वोटों से चुनाव जीतते।

बता दें कि विजयपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। जहां प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन्हें शुभकामनाएं दी।विजयपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।

**मुझसे कहा कि आप अपना फार्म खींच लेना-** कांग्रेस विधायक ने कहा- हमें कहा गया कि आप फार्म खींच लेना, मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है। हम स्वाभिमानी लोग हैं। इसके बाद पूरा चुनाव निकल गया, उन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। वे हमारे लोगों को डराते धमकाते रहे। मेरे सामने और कार्यकर्ताओं के सामने कई चुनौती आई थी। इस चुनाव से साबित हो गया कि किसी भी गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, क्षेत्र के लिए लड़ेगा तो कोई भी विधायक बन सकता है।

**हमारे कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया-** कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि चुनाव में हमारे लोगों को डराया धमकाया गया, क्योंकि वहां अधिक संख्या में आदिवासी वोटर हैं। लगभग 80 हजार के आसपास। उनकी सोच यह थी कि आदिवासी किसी नेता या वोटर को मार दिया जाए, जिससे मातम का माहौल हो जाए और कोई वोट डालने नहीं जाए। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने डकैतों को बुलाया, लोगों पर गोलियां चलवाई, कई गांव में गोलियां चली और लोगों के साथ मारपीट हुई। गुंडागर्दी और आतंक से चुनाव जीतने की कोशिश की गई। प्रशासन ने उन्हें खुली छूट दे रखी थी।

**नेता प्रतिपक्ष बोले-चुनाव में बीजेपी को चप्पल पड़ी-** मल्होत्रा ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी मुलाकात की। मल्होत्रा चप्पल पहनकर पहुंचे थे। वे नेता प्रतिपक्ष के पैर छूने के लिए झुके तो सिंघार ने उन्हें गले लगा लिया। विधायक से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- चप्पलें तो बीजेपी को पड़ी हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। हमारे विधायक भले ही हवाई चप्पल पहनते हैं लेकिन, बगैर चप्पल मारे जिस प्रकार बीजेपी को इस चुनाव में चप्पलें पड़ी हैं।

# एमपी में शादी हो या रैली सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे

## पुलिस ने रिकॉर्डिंग मांगी तो देनी होगी, ये कानून नहीं माना तो जुर्माना पक्का

**भोपाल (नप्र)।** मध्यप्रदेश सरकार लोक सुरक्षा कानून यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करने की तैयारी में है। इस कानून के तहत सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।

गृह विभाग ने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक, शादी चाहे मैरिज गार्डन में हो या निजी स्थान पर, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। किसी जगह 100 से एक हजार तक या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा।

इसके दायरे में कॉलेज, स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पतालों के साथ राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम, रैलियां और जुलूस भी आएंगे। नए एक्ट के मुताबिक, वीडियो फुटेज को दो महीने तक सुरक्षित रखना पड़ेगा। पुलिस के मांगने पर इसे देना भी पड़ेगा। सीसीटीवी लगाने का खर्च संबंधित प्रतिष्ठान या कार्यक्रम का आयोजक उठाएगा।

सरकार ने तीन महीने पहले इंदौर में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो सफल माना जा रहा है। नए कानून के ड्राफ्ट को परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी और इस नए कानून के ड्राफ्ट में क्या प्रावधान है।

### नए एक्ट के प्रावधान

- शादी मैरिज गार्डन में हो या निजी स्थान पर, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- यदि किसी स्थान पर 100 से एक हजार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा।
- संचालकों को सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को 2 माह के लिए सुरक्षित रखना जरूरी होगा।
- यदि विशेष स्थिति में पुलिस या जांच एजेंसी इसकी मांग करती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग को देना जरूरी होगा।
- संस्थान- प्रतिष्ठानों को खुद के खर्च पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।